



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

M-2
11/11/99

सं. 127]
No. 127]

नई दिल्ली, बुधवार, जून 2, 1999/ज्येष्ठ 12, 1921
NEW DELHI, WEDNESDAY, JUNE 2, 1999/JYAISTHA 12, 1921

वाणिज्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 जून, 1999

अंतिम निष्कर्ष

विषय :—जापान, कोरिया आर पी, टर्की, ताईवान, अमरीका, जर्मनी तथा फ्रांस से स्टीरन बूटाडियन रबड़ (एस. बी. आर.) के आयात के संबंध में पाटनरोधी जाँच अंतिम निष्कर्ष।

30/1/97-एडिडी.—कस्टम टैरिफ अधिनियम, 1975 (1995 में यथासंशोधित) तथा उसकी कस्टम टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन एवं संग्रहण और क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 को ध्यान में रखते हुए :

क. पद्धति

1. आरंभिक निष्कर्षों के बाद नीचे दी गयी पद्धति का पालन किया गया है:—

(क) नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी (जिसे इसमें इसके बाद प्राधिकारी कहा गया है) ने जापान, कोरिया आर पी, टर्की, ताईवान, अमरीका, जर्मनी तथा फ्रांस से स्टीरन बूटाडियन रबड़ (एस. बी. आर.) के आयात के संबंध में पाटनरोधी जाँच संबंधी अधिसूचना, तारीख 21-1-99 द्वारा आरंभिक निष्कर्ष अधिसूचित किये और हितबद्ध पार्टियों से अपने विचार लिखित रूप में, इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 40 दिनों के भीतर देने के लिए कहा;

(ख) प्राधिकारी ने आरंभिक निष्कर्षों की एक प्रति उन ज्ञात हितबद्ध पार्टियों को भेजी जिनसे आरंभिक निष्कर्षों पर अपने विचार, पत्र की तारीख से 40 दिनों के भीतर देने का अनुरोध किया गया था;

(ग) प्राधिकारी ने नई दिल्ली में जापान, कोरिया आर पी, टर्की, ताईवान, अमरीका, जर्मनी और फ्रांस के दूतावासों को आरंभिक निष्कर्षों की एक प्रति इस अनुरोध के साथ भेजी की वे निर्यातकों तथा अन्य हितबद्ध पार्टियों से आरंभिक निष्कर्षों पर अपने विचार देने के लिए कहें;

(घ) प्राधिकारी ने, आरंभिक निष्कर्षों की अधिसूचना जारी होने से पहले सभी हितबद्ध पार्टियों को अपने विचार मौखिक रूप से प्रस्तुत करने का अवसर 10-11-1998 को दिया गया था। आरंभिक निष्कर्षों की अधिसूचना के बाद प्राधिकारी ने निर्यातकों को 25-2-99 को और वादी, आयातक तथा अन्य हितबद्ध पार्टियों को अपने विचार मौखिक रूप से रखने का अवसर 26-2-99 को दिया। अपने विचार मौखिक रूप से देने वाली सभी पार्टियों से, मौखिक रूप से दिए गए अपने विचारों को लिखित रूप में देने का अनुरोध किया गया। पार्टियों से, विपक्षी पार्टियों द्वारा व्यक्त किये गए विचारों की प्रतियाँ लेने और उनके उत्तर, यदि कोई हों, देने का अनुरोध किया गया;

(ङ) प्राधिकारी ने विभिन्न हितबद्ध पार्टियों द्वारा दिए गए साक्ष्यों एवं तर्कों के अगोपनीय रूपों वाली एक सार्वजनिक फाईल, सभी हितबद्ध पार्टियों के लिए उपलब्ध कराई। उन सभी पार्टियों को इस सार्वजनिक फाईल को देखने की अनुमति दी गयी जिन्होंने इसके लिए लिखित रूप में अनुरोध किया था;

(च) आरंभिक निष्कर्षों की घोषणा से पहले हितबद्ध पार्टियों द्वारा दिए गए तर्कों, जो अधिसूचित आरंभिक निष्कर्षों में दिए गए हैं, को संक्षिप्तता की दृष्टि से यहां दोहराया नहीं जा रहा है। तथापि, हितबद्ध पार्टियों द्वारा दिए गए तर्कों को आरंभिक निष्कर्षों और/या इन निष्कर्षों में उचित रूप से लिया गया है;

(छ) पूर्वोक्त नियम 16 के अनुसार इन निष्कर्षों के लिए आवश्यक समझे गए अनिवार्य तथ्य/आधार, ज्ञात हितबद्ध पार्टियों को बता दिए गए थे और उन पर प्राप्त टिप्पणियों को इन निष्कर्षों में उपयुक्ततः लिया गया है;

(ज) जाँच पूरी करने के लिए प्राधिकारी ने केन्द्रीय सरकार से 2 महीने के समय की वृद्धि मांगी थी जिसे केन्द्रीय सरकार ने मंजूर कर दिया था। इस बढ़ी हुई अवधि में जाँच पूरी कर ली गयी है।

(झ) **इस अधिसूचना में यह चिन्ह एक हितबद्ध पार्टी द्वारा गोपनीय आधार पर दी गयी सूचना का द्योतक है और नियमों के अधीन प्राधिकारी द्वारा इसे ऐसा माना गया है।

ख. जाँच का आरंभ

2. प्राधिकारी ने जापान, कोरिया आर पी., टर्की, ताईवान, अमरीका, जर्मनी और फ्रांस मूल के या वहां से आयातित, कस्टमस टैरिफ अधिनियम, 1975 की अनुसूची 1 के कस्टम कोड 4002.19 के अंतर्गत वर्गीकृत एस बी आर के आयातों के संबंध में पाटनरोधी जाँच आरंभ करते हुए एक सार्वजनिक सूचना तारीख 7 अप्रैल, 1998 भारत के राजपत्र, आसाधारण में जारी की।

आयातक द्वारा दिया गया तर्क

3. वादी सामान्य मूल्य पर साक्ष्य देने में असफल रहा है तथा अनेक अनुमानों एवं कल्पनाओं पर आधारित रहा है। वादी द्वारा दिया गया आवेदन त्रुटिपूर्ण था क्योंकि कोरिया आर पी के लिए एस बी आर के सामान्य मूल्य का कोई साक्ष्य नहीं था और वादी कोरिया आर पी से पाटन का प्रथम दृष्टया साक्ष्य प्रस्तुत करने में असफल रहा है। प्राधिकारी को वादी द्वारा दिए गए साक्ष्य की यथार्थता और पर्याप्तता की जाँच किए बिना ही प्राधिकारी ने जाँच आरंभ कर दी थी। अतः जाँच आरंभ से ही अमान्य है।

प्राधिकारी द्वारा जाँच

4. वादी द्वारा दायर की गयी याचिका से यह पता लगता है कि सामान्य मूल्य और निर्यात मूल्य संबंधी सूचना सभी देशों के संबंध में दी गयी थी। ऐसे मूल्य/कीमत का हिसाब लगाने का आधार भी याचिका में दिया गया था। वादी को दोषम सूचना पर विश्वास करने का भी अधिकार है जो सार्वजनिक रूप से उपलब्ध है।

यथार्थ सूचना के अभाव में नियम, सामान्य मूल्य एवं निर्यात मूल्य निर्मित करने की अनुमति देते हैं। इसके बाद जाँच के दौरान वादी द्वारा दी गई सूचना पर सभी हितबद्ध पार्टियों को टिप्पणियाँ करने के अवसर दिए गए जिन पर प्राधिकारी ने भली प्रकार विचार किया है।

यह कहना गलत है कि प्राधिकारी ने सूचना की यथार्थता और पर्याप्तता जाँचे बिना जाँच आरंभ कर दी थी। आरंभिक अधिसूचना में प्राधिकारी ने समान वस्तुओं, स्वदेशी उद्योग, पाटन, क्षति एवं कारणात्मक संबंध पर आवश्यक सूचना स्पष्ट रूप से दी थी। यह कहना भी गलत है कि वादी, पाटन पर प्रथम-दृष्टया साक्ष्य देने में असमर्थ रहा है। वादी ने याचिका में दिया है कि कैसे सामान्य मूल्य, निर्यात मूल्य एवं पाटन मार्जिन के दावे किए गए हैं। चूंकि वादी ने जाँच आरंभ करने के लिए आवश्यक सूचना उपलब्ध करा दी थी, प्राधिकारी ने संतुष्ट होने पर, नियमों के अनुसार जाँच आरंभ कर दी थी और इसलिए प्राधिकारी का मानना है कि आरंभ में की गई जाँच वैध है और आदितः अमान्य नहीं है।

ग. विचाराधीन उत्पाद

5. वर्तमान जाँच में संबंधित उत्पाद विषयगत देशों के मूल का या वहां से निर्यातित स्टीरीन बुटाडियन रबर (एसबीआर) है जो कस्टम टैरिफ अधिनियम के कस्टम उप-शीर्ष 4002.19 के अंतर्गत वर्गीकृत और जो 21 जनवरी, 1999 के आरंभिक निष्कर्षों के पैरा 5 में स्पष्ट किया गया है। प्राधिकारी ने अन्य बातों के साथ-साथ पैरा 5 में माना है कि विचाराधीन उत्पाद, कस्टम टैरिफ अधिनियम के कस्टम उप शीर्ष 4002.19 के अंतर्गत 1500 श्रृंखला, 1700 एवं 1900 श्रृंखला का एस बी आर है।

वादी द्वारा दिया गया तर्क

6(क) 1900 श्रृंखला का एस बी आर भी कस्टम टैरिफ के अध्याय 39 के अंतर्गत आयात किया जा रहा है और परिणामतः प्राधिकारी को केवल अध्याय 40 ही नहीं अपितु अध्याय 39, प्रविष्टि सं० 3903.90 (मूल रूपों में स्टीरीन के पॉलीमर्स-अन्य) पर भी विचार करना चाहिए। एक बार उत्पाद की एस बी आर के रूपों में पहचान हो जाने पर, जिस कस्टम कोड के अंतर्गत उत्पाद आयात किया गया है, उसका ध्यान किए बिना ही उत्पाद के सभी आयातों पर पाटन रोधी सीमा-शुल्क लगाया जाना है सीमा-शुल्क लगाने के लिए उत्पाद के दायरे को संशोधित किया जाना आवश्यक है। वादी ने आरोप लगाया है कि 1900 श्रृंखला की हाई स्टीरीन रबड़ कस्टम कोड अध्याय 39 के अंतर्गत के एच एस 68 के ट्रेड नाम से और कोरिया आर पी के अध्याय 40 के अंतर्गत आयात किया गया है।

आयातक एवं निर्यातक द्वारा तर्क

6(ख) वादी का अभिवेदन त्रुटिपूर्ण है। कस्टम टैरिफ के अध्याय 39 में विशिष्ट रूप से दिया गया है कि अध्याय 40 में यथा परिभाषित कृत्रिम रबड़ या उससे बनी वस्तुएं अध्याय 39 में कवर नहीं होती हैं परिणामतः यदि इन देशों से आयातित एस बी आर, कृत्रिम रबड़ (अध्याय 40 की टिप्पणी 4 द्वारा) की परिभाषा को संतुष्ट नहीं करता है तो वह कृत्रिम रबड़ नहीं रहेगा और प्लास्टिक की वस्तुएं ही मानी जाएंगी। एस बी आर 1900 श्रृंखला, जैसा

कि यह संज्ञा स्वयं ही बताती है, एक कृत्रिम रबड़ है और प्लास्टिक की वस्तु नहीं है। कोरिया आर पी से निर्यातक का कहना है कि कोसिन के एच एच 68 एल पॉलीमर रेजिन है और यह अध्याय 39 के अंतर्गत है क्योंकि इसमें 60% स्टरिन एवं लगभग 32% बूटाडियन होता है।

प्राधिकारी द्वारा जाँच

7. प्राधिकारी का मानना है कि आरंभिक निष्कर्षों में अन्य बातों के साथ-साथ यह माना गया था कि वर्तमान जाँच में संबंधित उत्पाद, विषयगत देशों के मूल का या वहां से निर्यातित स्टीरिन बूटाडियन रबड़ (एस बी आर) है जो कस्टम टैरिफ अधिनियम के कस्टम उपशीर्ष 4002.19 के अंतर्गत वर्गीकृत एवं जो 21 जनवरी, 1999 के आरंभिक निष्कर्षों के पैरा 5 में स्पष्ट किया गया है। प्राधिकारी ने अन्य बातों के साथ-साथ माना है कि विचाराधीन उत्पाद, कस्टम टैरिफ अधिनियम के कस्टम उपशीर्ष 4002.19 के अंतर्गत 1500 श्रृंखला, 1700 श्रृंखला तथा 1900 श्रृंखला का एस बी आर है। हितबद्ध पार्टियों में से किसी ने भी इस संबंध में कोई विवाद नहीं किया है और इसलिए प्राधिकारी इस संबंध में अपने आरंभिक निष्कर्षों की पुष्टि करता है।

प्राधिकारी नोट करता है कि वादी दावा कर रहा है कि एस बी आर कस्टम अध्याय 39 प्रविष्टि नं० 3903.90 (मूल रूपों में स्टीरिन के पॉलीमर्स) के अंतर्गत छोड़ा (क्लीयर) जा रहा है और इसलिए इस शीर्ष के अंतर्गत भी पाटन रोधी सीमा-शुल्क लगाया जाना चाहिए। इसके विपरीत निर्यातक एवं आयातक का कहना है कि अध्याय 39 प्लास्टिक से संबंधित है और एस बी आर इसके अंतर्गत नहीं आता तथा अध्याय 39 प्रविष्टि नं० 3903.90 के अंतर्गत आने वाले उत्पादों पर सीमा-शुल्क नहीं लगाया जाना चाहिए। प्राधिकारी का विचार है कि अध्याय 39 के अंतर्गत "प्लास्टिक एवं उसकी वस्तुएं" आती हैं जबकि अध्याय 40 में "रबड़ एवं उसकी वस्तुएं" आती हैं। स्टीरिन बूटाडियन रबड़, जैसा कि नाम से पता चलता है, एक कृत्रिम रबड़ है और अध्याय 40 के अंतर्गत आता है। यह भी विचार है कि अध्याय 39 के नोट सं० 2(4) के अनुसार अध्याय 40 में आने वाली कृत्रिम रबड़ या उसकी वस्तुएं अध्याय 39 के अंतर्गत कवर नहीं होती हैं। यह भी विचार है कि आयात आंकड़े देते समय वादी ने केवल कस्टम शीर्ष 4002.19 के संबंध में ही सूचना दी थी। यह साक्ष्य देते हुए कि एस बी आर 1900 श्रृंखला भी अध्याय 39 के अंतर्गत आयात की जा रही है, प्राधिकारी का कहना है कि अध्याय 39 के अंतर्गत क्लीयर की गई वस्तुएं इलास्टोमर रेजिन के एच एस 68 है और इस प्रकार यह कृत्रिम रबड़ की संज्ञा के अंतर्गत नहीं है। इस को देखते हुए प्राधिकारी के पास पाटन रोधी सीमा-शुल्क लगाने के प्रयोजन के लिए, उप शीर्ष 3903.90 के अंतर्गत आने वाली मदों को कवर करने का औचित्य नहीं है।

तथापि, प्राधिकारी वादी के इस तर्क से इस सीमा तक सहमत है कि कस्टम शीर्ष का ध्यान किए बिना विचाराधीन उत्पाद, यद्योक्त विनिर्दिष्ट श्रृंखलाओं का कृत्रिम बूटाडियन रबड़ है। इस प्रकार प्राधिकारी का मानना है कि वर्तमान मामले में पाटनरोधी सीमा-शुल्क लगाने के प्रयोजन के लिए, उप-शीर्ष 3903.90 के अंतर्गत आने वाली सभी मदों को कवर करने का औचित्य नहीं है, फिर भी यद्योक्त विनिर्दिष्ट श्रृंखलाओं के स्टीरिन बूटाडियन रबड़ पर पाटनरोधी सीमा-शुल्क देय है, चाहे इसे कस्टम टैरिफ अधिनियम के किसी अन्य शीर्ष के अंतर्गत क्लीयर कराने के लिए कहा गया हो। यदि छुड़वाई (क्लीयरेंस) के लिए प्रस्तुत माल सही प्रकार से वर्गीकृत नहीं है तो प्राधिकारी माल को सही प्रकार से वर्गीकृत करने को स्वतंत्र है और उससे यह आशा भी की जाती है।

घ. समान वस्तुएं

8. प्राधिकारी नोट करता है कि आरंभिक निष्कर्षों की अधिसूचना जारी होने के बाद किसी भी हितबद्ध पार्टी द्वारा इस संबंध में कोई दलील नहीं दी गयी है। अतः प्राधिकारी इस संबंध में अपने आरंभिक निष्कर्षों की पुष्टि करता है।

ऊ. स्वीदेशी उद्योग

9. प्राधिकारी नोट करता है कि आरंभिक निष्कर्षों की अधिसूचना जारी होने के बाद किसी भी हितबद्ध पार्टी द्वारा इस संबंध में कोई विवाद नहीं किया गया है। अतः प्राधिकारी इस सूचना में अपने आरंभिक निष्कर्षों की पुष्टि करता है।

च. पाटन

10. पाटन से संबंधित नियमों पर, आरंभिक निष्कर्षों में खर्चा हो चुकी है। आरंभिक निष्कर्षों के बाद निर्यातकों द्वारा दिए गए अभिवेदन एवं प्राधिकारी द्वारा उनकी जाँच नीचे दिए गए के अनुसार है :

(I) देश-अमरीका

निर्यातक-अमेरीपोल सिनपोल कार्पोरेशन

निर्यातक ने निवेदन किया है कि वर्ग 8401, 1700 श्रृंखला के अंतर्गत आता है किन्तु यह बात भी रखी है कि यह विचाराधीन उत्पाद के समान वस्तु नहीं है और वे विश्व में इसके एकमात्र उत्पादक हैं।

उन्होंने आरंभिक निष्कर्षों में माने गए के अनुसार लागत संबंधी सूचना अभी तक नहीं दी है और इसलिए, सामान्य मूल्य के संबंध में उनके द्वारा दी गई सूचना को स्वीकार नहीं किया जा सकता। अतः प्राधिकारी, आरंभिक निष्कर्षों में निश्चित किए गए के अनुसार निर्यात पर 30.55% के पाटन मार्जिन की पुष्टि करता है।

(II) देश-फ्रांस

निर्यातक : बेयर

उन्होंने पाटन मार्जिन का हिसाब लगाने के संबंध में और आगे कोई सूचना नहीं दी है और इसलिए प्राधिकारी, आरंभिक निष्कर्षों में निश्चित किए गए के अनुसार निर्यात मूल्य से 28.20% के पाटन मार्जिन की पुष्टि करता है।

(III) देश-जर्मनी

निर्यातक-बी एस एल

उन्होंने पाटन मार्जिन का हिसाब लगाने के संबंध में और आगे कोई सूचना नहीं दी है और इसलिए प्राधिकारी, आरंभिक निष्कर्षों में निश्चित किए गए के अनुसार निर्यात मूल्य के 24.86% के पाटन मार्जिन की पुष्टि करता है।

(IV) देश-ताइवान

निर्यातक-ताइवान सिन्थेटिक रबड़ कार्पोरेशन

निर्यातक ने, पहले आरंभिक निष्कर्षों में निश्चित किए गए के अनुसार आयातित पाटन मार्जिन के संबंध में और आगे कोई सूचना नहीं दी है। और भी, उन्होंने आरंभिक निष्कर्षों में निश्चित किए गए के अनुसार पाटन मार्जिन की न तो पद्धति और ना ही हिसाब लगाने का प्रतिवाद किया है। अतः प्राधिकारी, आरंभिक निष्कर्षों में निश्चित किए गए के अनुसार एस बी आर 1502 वर्ग के निर्यात मूल्य पर 6.68% तथा एस बी आर 1712 वर्ग के संबंध में निर्यात मूल्य पर 6.07% के पाटन मार्जिन की पुष्टि करता है।

(V) देश-टर्की

निर्यातक-पेटकिम होल्डिंग ए एस

तारीख 25-2-99 को आम सुनवाई के दौरान उनके अनुरोध पर निर्यातक को, पाटन मार्जिन का हिसाब लगाने की पद्धति और हिसाब लगाने के लिए प्रयुक्त आंकड़े स्पष्ट किए गए थे। उसके बाद निर्यातक ने स्वदेशी मूल्य पर अपने दावे में संशोधन किया है और एक निम्नतर पाटन-मार्जिन की मांग की है। यह दावा किया गया है कि टर्की में मुद्रा-स्थिति की दर ऊंची है जिसके कारण 5.8% मासिक के मूल्य समायोजन की आवश्यकता होती है। और आगे यह दावा भी किया गया है कि प्रश्नावली के उत्तर में घोषित स्वदेशी मूल्य, उधार सुविधाओं के लिए ब्याज की दर सहित सभी लागू मूल्यों के औसत थे जबकि घोषित निर्यात मूल्य में ब्याज की दर शामिल नहीं थी। इसके अलावा भारतीय बाजार को निर्यात, परियात्मक मूल्यों पर किए गए थे।

उन्होंने मुद्रा-स्थिति के प्रभाव का दावा करते हुए स्वदेशी मूल्य में संशोधन किया है और अनुरोध किया है कि इसके कारण, एस 1502 वर्ग के लिए उसके पहले आरंभिक निष्कर्षों में निश्चित किए गए पाटन मार्जिन को 28.82% से बदल कर 12.47% कर दिया जाए तथा एस 1712 के लिए पहले आरंभिक निष्कर्षों में निश्चित किए गए 13.66% के पाटन मार्जिन को बदल कर 9% कर दिया जाए। तथापि, उन्होंने अपने दावे को पुष्ट करने के लिए कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है। उन्होंने अपने दावों में और आगे संशोधन किया है तथा एस 1502 वर्ग के लिए पाटन-मार्जिन 14.06% और एस 1712 वर्ग के लिए 6.65% संशोधित कर देने का अनुरोध किया है।

प्राधिकारी द्वारा जाँच

प्राधिकारी ने पाया है कि निर्यातक ने आरंभिक निष्कर्षों के अधिसूचित होने और प्राधिकारी के निर्यातकों के साथ मौखिक सुनवाई कर लेने के बाद, ऊपर स्पष्ट किए गए के अनुसार स्वदेशी मूल्यों में संशोधन किया है। उन्होंने डिस्कलोजर विवरण जारी होने के बाद स्वदेशी मूल्यों पर अपने दावे को भी संशोधित किया है। मौखिक सुनवाई में ही निर्यातकों ने यह नहीं बताया था कि वे सामान्य मूल्य निश्चित करने के प्रयोजन के लिए अपने स्वदेशी मूल्य में संशोधन करेंगे। इस प्रकार प्राधिकारी नोट करता है कि संशोधित सूचना इतनी देर से दी गई है कि अन्य हितबद्ध पार्टियों को ऐसी सूचना पर टिप्पणी देने का उचित अवसर नहीं मिला है। और भी, संशोधित सूचना साक्ष्य से पुष्ट भी नहीं है। यह विचार करते हुए कि सूचना समय पर नहीं दी गई है और उनकी पुष्टि भी नहीं दी गई है, प्राधिकारी सूचना की जाँच करना उचित नहीं समझता और ऊपर स्पष्ट किए गए कारणों से दी गई संशोधित सूचना को अनदेखा करने के लिए विवश है। इसको देखते हुए प्राधिकारी एस बी आर 1502 वर्ग के संबंध में निर्यात मूल्य के 28.2% तथा एस 1712 के निर्यात मूल्य के 13.66% के पाटन मार्जिन, जैसा कि आरंभिक निष्कर्षों में निश्चित किया गया था, की पुष्टि करता है।

(1) देश-कोरिया

निर्यातक-कोरिया कुम्हो पैट्रोकेमिकल्स लिमिटेड

सत्यापन के दौरान निर्यातक को, आरंभिक निष्कर्षों में यथा निश्चित किए गए, पाटन मार्जिन का हिसाब लगाने में प्रयुक्त पद्धति और आंकड़े, स्पष्ट कर दिए गए थे और जिन पर कोई विवाद नहीं किया गया है। अपने बाद के अभिवेदनों में उन्होंने भंडारण, तकनीकी सेवाओं, सर्वद्वानात्मक यात्रा, अप्राप्य ऋण, खर्चों तथा विज्ञापन के लिए दावों की अनुमति का अनुरोध किया गया था जिनकी, सामान्य मूल्य निश्चित करते हुए पहले अनुमति नहीं दी गई थी। पड़ताल के दौरान, सामान्य मूल्य निश्चित करते हुए उन्होंने अनुसंधान और विकास खर्चों तथा दान के लिए दावे किए हैं और यह भी कहा है कि वे ब्याज के लिए दावा करेंगे, जिसका विवरण अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है। कुछ दावों के लिए उन्होंने प्रतिटन राशि में संशोधन किया है जिनकी अनुमति पहले दे दी गई थी। अपने संशोधित दावों के आधार पर उन्होंने न्यूनतम पाटन मार्जिन मांगा है।

प्राधिकारी द्वारा जाँच

सामान्य मूल्य

सामान्य मूल्य का हिसाब स्वदेशी मूल्य के भारत औसत के आधार पर लगाया जाता है प्राधिकारी छूट, उधार ब्याज, बैंकिंग, अंतर्देशीय भाड़े और पड़ताल के दौरान सत्यापित करों पर समायोजन की अनुमति देता है। तकनीकी सेवाओं, सर्वद्वानात्मक यात्रा खर्चों, अनुसंधान एवं विकास खर्चों तथा विज्ञापन

के लिए समायोजन के दावे अनुमत नहीं हैं क्योंकि यह बात प्रमाणित नहीं है कि इन खर्चों का लाभ किस प्रकार स्वदेशी बाजार तक ही सीमित है। भंडारण के लिए समायोजन को अनुमत नहीं किया गया है क्योंकि यह उत्पादन के बाद का खर्च है। अप्राम्य ऋणों के लिए समायोजन की अनुमति नहीं दी गई है क्योंकि बिक्री के समय में इन खर्चों की प्रासंगिकता ज्ञात नहीं है। दान के लिए समायोजन अनुमत नहीं है क्योंकि यह अकार्य खर्च है। हैंडलिंग के लिए समायोजन की अनुमति नहीं दी गई क्योंकि जाँच के दौरान इसकी पुष्टि नहीं हुई। इस प्रकार एस बी आर 1502 वर्ग के लिए सामान्य मूल्य अमरीकी डालर XXX प्रति मीटरिक टन तथा एस बी आर 1712 वर्ग के लिए अ.डा.XXX के सामान्य मूल्य निश्चित किये जाते हैं।

निर्यात मूल्य : निर्यात मूल्य का हिसाब भारत को की गई निर्यात बिक्रियों के भारत औसत के आधार पर लगाया गया है। छूट/कमीशन, पैकिंग, अंतर्देशीय, भाड़े, निरीक्षण शुल्क, विदेशी भाड़े एवं विदेशी बीमे के लिए मांगे गए समायोजन अनुमत कर दिए गए हैं, जैसा कि सत्यापन के दौरान सत्यापित किया गया था। एस बी आर 1502 वर्ग के लिए XXX अमरीकी डालर प्रति मीटरिक टन तथा एस बी आर 1712 वर्ग के लिए XXX अमरीकी डालर प्रति मीटरिक टन का निर्यात मूल्य तय किया जाता है। एस बी आर 1502 वर्ग के लिए अमरीकी डालर XXX प्रति मी. टन का पाटन मार्जिन आकलित किया जाता है जो निर्यात मूल्य का 16.82% है और एस बी आर 1712 वर्ग के लिए अ.डा.XXX प्रति मी. टन का लगाया जाता है जो निर्यात मूल्य का 10.94% है।

निर्यातक के भारत में प्राधिकृत प्रतिनिधि ने सूचना की गोपनीयता को समाप्त करने का अनुरोध किया है। तथापि, निर्यातक ने फिर भी गोपनीयता बनाए रखने का अनुरोध किया है। चूंकि निर्यातक ने गोपनीयता समाप्त नहीं की है, प्राधिकारी ने सूचना को, जहाँ कहीं भी इसे गोपनीय मानने के लिए कहा गया था, गोपनीय मानना उचित समझा है।

(VII) देश-जापान

निर्यातक-जे एस आर कार्पोरेशन

सत्यापन के दौरान निर्यातक को, आरंभिक निष्कर्षों में निश्चित किए गए के अनुसार, पाटन मार्जिन का हिसाब लगाने में प्रयुक्त पद्धति और आँकड़े स्पष्ट कर दिए गए थे और जिन पर कोई विवाद नहीं किया गया है। अपने बाद के अभिवेदनों में, उन्होंने स्वदेशी बाजार के लिए उत्पादित अतिरिक्त वर्गों के लिए अपने दावे को अनुमति देने का अनुरोध किया है जिसे आरंभिक निष्कर्षों में प्राधिकारी ने अनुमति नहीं दी थी। सत्यापन के दौरान उन्होंने इस तथ्य पर भी समायोजन की मांग की थी कि जहाँ निर्यात बिक्री में, बिक्री एजेंट के माध्यम से की जाती है जिसे कमीशन मिलता है, वहाँ स्वदेशी बाजार में बिक्री सीधे ग्राहकों को की जाती है और इसलिए व्यापार के स्तर में भिन्नता है। माँग की गई है कि निर्यात बिक्रियों के लिए दिया गया कमीशन, स्वदेशी बिक्रियों के मामले में भी बराबर अनुमत होना चाहिए। उन्होंने न्यूनतम (डी-मिनिमस) पाटन मार्जिन का दावा किया है।

प्राधिकारी द्वारा जाँच

सामान्य मूल्य :

सामान्य मूल्य का हिसाब, स्वदेशी बाजार में भारत औसत मूल्य पर लगाया गया है। सत्यापन के दौरान यथा सत्यापित अंतर्देशीय भाड़े, बीमे और ब्याज के लिए समायोजन की अनुमति दे दी गई है। भंडारण लागत के लिए दावा नहीं माना गया है क्योंकि यह उत्पादन के बाद का खर्च है। स्वदेशी बाजार के लिए उत्पादित अतिरिक्त वर्गों के लिए माँग, आकलनों पर आधारित है और यह निर्यातक द्वारा वास्तव में खर्च नहीं किए गए हैं। अतः इनके लिए अनुमति नहीं दी गई है। यह माँग सत्यापन के दौरान भी साक्ष्यों से प्रमाणित नहीं की गई थी। व्यापार के स्तर में भिन्नता के कारण कमीशन के लिए समायोजन, स्वीकार नहीं किया गया है क्योंकि यह आकलन पर आधारित है और निर्यातक द्वारा वास्तव में खर्च नहीं किया गया है।

निर्यात मूल्य

सत्यापन के दौरान यथा सत्यापित निर्यात मूल्य का हिसाब, भारत औसत मूल्य के आधार पर लगाया गया है। जापानी ट्रेडिंग हाउस, भारतीय एजेंटों को दिए गए कमीशन, अंतर्देशीय भाड़े, बीमे, विदेशी भाड़े और बीमे, ब्याज और कमीशन के लिए दावे को स्वीकार कर लिया गया है। ग्रेड 1500 के लिए पाटन मार्जिन अ.डा.XXX है जो निर्यात मूल्य का 3.36% है, ग्रेड 1502 के लिए अ.डा.XXX प्रति मी.टन का पाटन मार्जिन तय किया जाता 17.32% है और एस 1712 ग्रेडों के लिए XXX अ.डा. प्रति मी. टन तय किया जाता है, जो निर्यात मूल्य का 7.64% है।

11. अ. सहयोगी निर्यातकों के संबंध में पाटन मार्जिन एवं पाटन संबंधी अन्य मामले, आगे के पैराग्राफों में लिए गए हैं।

वादी द्वारा दिया गया तर्क

12. प्राधिकारी ने केवल एक या दो निर्यातकों द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों और उनके उत्तरों के आधार पर, एक देश के अ. सहयोगी निर्यातकों सहित सभी निर्यातकों पर एक समान सीमा-शुल्क की सिफारिश की है। कुछ आयातक, उच्चतर पाटन मार्जिन के साथ पाटन कर रहे होंगे जैसा कि वादी ने दावा किया है। अतः वादी द्वारा अपनी याचिका में स्थापित पाटन-मार्जिन के बराबर का पाटन रोधी सीमा-शुल्क उन सभी निर्यातकों पर लगाया जाना चाहिए जिन्होंने उत्तर नहीं दिया है या अ. सहयोगी हैं।

प्राधिकारी द्वारा जाँच

प्राधिकारी ने विपयगत देशों से उन-असहयोगी निर्यातकों के बारे में, जिन्होंने प्रश्नावली का उत्तर नहीं दिया है, आरंभिक निष्कर्षों में प्रत्येक देश से सहयोगी निर्यातकों के लिए निश्चित किया गया उच्चतम पाटन-मार्जिन निश्चित किया है। इस प्रकार ताइवान से अ. सहयोगी निर्यातकों के लिए फैक्ट्री-एतर निर्यात मूल्य के प्रतिशत के रूप में पाटन मार्जिन ताइवान के लिए 6.68%, टर्की के लिए 28.82%, कोरिया के लिए 11.66% एवं जापान के लिए 17.32% निश्चित किया गया था।

प्राधिकारी नोट करता है कि केवल वादी ही नहीं अपितु कुछ सहयोगी निर्यातकों की भी राय है कि, उनके अ-सहयोगी रवैये के लिए, असहयोगी निर्यातकों को किसी भी तरह से लाभ नहीं होना चाहिए। प्राधिकारी का भी यही विचार है और इसलिए वह वादी द्वारा अपनी याचिका में अ-सहयोगी निर्यातकों के मामले में माँगे गए के अनुसार पाटन-मार्जिन निश्चित करता है। इस प्रकार अमरीका, फ्रांस, जर्मनी, ताइवान, टर्की, कोरिया आर पी और जापान के अ-सहयोगी निर्यातकों के मामले में क्रमशः 30.55%, 28.20%, 24.86%, 9.21%, 77.6%, 18.78% तथा 90.79% का पाटन मार्जिन निश्चित किया जाता है। तथापि, पाटन-रोधी सीमा-शुल्क, कानून के अनुसार लगाया जाता है जो पाटन मार्जिन एवं क्षति मार्जिन का निम्नतर प्रदान करता है।

वादी द्वारा दिया गया तर्क

14. पाटन मार्जिन निश्चित करने में निर्यातक द्वारा माँगे गए समायोजन प्यादा (ऊँचे) लगते हैं। कोरियाई निर्यातक एवं इसके स्थानीय एजेंट आधारहीन तथा गलत समायोजन माँग कर प्राधिकारी को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। प्राधिकारी ने आरंभिक निष्कर्षों में कुछ समायोजनों को नहीं मान कर ठीक किया है। तथापि, प्राधिकारी द्वारा अनुमत निर्यातक के बैंकिंग और अन्य समायोजन, कम्पनी द्वारा वास्तविक किए गए खर्च पर आधारित प्रतीत नहीं होते।

प्राधिकारी द्वारा जाँच

15. वादी का तर्क सामान्य प्रकृति का है और यह तथ्य एवं साक्ष्य से प्रमाणित नहीं है। प्राधिकारी ने जापान और कोरिया आर.पी. के निर्यातकों के बारे में सूचना का उस सीमा तक सत्यापन किया, जितना उसने आवश्यक समझा। दावों (माँगों) की जाँच पर ऊपर चर्चा हो चुकी है। प्राधिकारी मानता है कि संबंधित पैराग्राफों में चर्चित के अनुसार दावों (माँगों) को मानना उचित है क्योंकि वे प्राधिकारी द्वारा सूचना के सत्यापन पर आधारित हैं।

वादी द्वारा दिया गया तर्क

16. हाल के निर्णय में, अमरीकी सरकार ने दक्षिण कोरिया, ब्राजील एवं मैक्सिको में एस बी आर के उत्पादकों पर पाटन-रोधी सीमा-शुल्क लगा दिया है। कोरिया के कुछ उत्पादकों पर लगाए गए सीमा-शुल्क की मात्रा एफ ओ बी मूल्य के 119% की है जिससे संकेत मिलता है कि लगाए जाने वाले पाटन-रोधी सीमा-शुल्क की मात्रा काफी बढ़ाई जानी चाहिए क्योंकि दो पाटन-रोधी प्राधिकारियों द्वारा मूल्यों का आकलन करते समय कोई महत्वपूर्ण अंतर नहीं हो सकता।

प्राधिकारी द्वारा जाँच

17. वादी ने अपने दावे को प्रमाणित नहीं किया है। प्राधिकारी ने पाटन मार्जिन का हिसाब लगाने की अपनी पद्धति पहले ही स्पष्ट कर दी है और उसको चुनौती नहीं दी गई है और जो पाटन-रोधी नियमावली के अनुसार है। प्राधिकारी जाँच की अवधि, विचाराधीन, उत्पाद, सामान्य मूल्य, निर्यात मूल्य आदि सम्बद्ध आवश्यक विवरणों के अभाव में दो भिन्न देशों के संबंध में पाटन मार्जिन की तुलना करना उचित नहीं समझता।

18. उपरोक्त के आधार पर पाटन-मार्जिन निम्नलिखित के अनुसार निश्चित किया जाता है :—

	देश	निर्यातक	वर्ग	निर्यात मूल्य के % के रूप में पाटन मार्जिन
1.	अमरीका	सभी निर्यातक	सभी वर्ग	30.55
2.	फ्रांस	सभी निर्यातक	सभी वर्ग	28.20
3.	जर्मनी	सभी निर्यातक	सभी वर्ग	24.86
4.	ताइवान	(i) ताइवान सिंथेटिक रबड़ कार्पोरेशन	एस 1502 एस 1712	6.68 6.07
		(ii) अन्य निर्यातक	सभी वर्ग	9.21
5.	टर्की	(i) पैटकिन पैट्रोकिन्या	एस 1502 एस 1712	28.82 13.66
		(ii) अन्य निर्यातक	सभी वर्ग	77.60
6.	कोरिया आरपी	(i) कोरिया कुम्हो	एस 1502 एस 1712 शृंखला	16.82 10.94
		अन्य निर्यातक	सभी वर्ग	18.78
7.	जापान	(i) जे एस आर कार्पो.	एस 1500 एस 1502 एस 1712	3.36 17.32 7.64
		(ii) अन्य निर्यातक	सभी वर्ग	90.79

टिप्पणी : किसी भी सहयोगी निर्यातक ने 1900 शृंखला एस बी आर के संबंध में सूचना नहीं दी है। अतः 1900 शृंखला एस बी आर के लिए वे 'अन्य निर्यातक' श्रेणी में आएंगे।

क्षति एवं कारणात्मक संबंध

19. क्षति एवं तथा कारणात्मक संबंध से सम्बद्ध नियमों पर आरंभिक निष्कर्षों में चर्चा हो चुकी है। क्षति करने वाले विभिन्न कारकों और कारणात्मक संबंध की स्थापना पर भी आरंभिक निष्कर्षों में चर्चा हो चुकी है।

20. आयातकों/निर्यातकों/अन्य हितबद्ध पार्टियों द्वारा निम्नलिखित तर्क दिए गए हैं :

- (i) इस मुद्दे का निश्चयन कि क्या विपयगत देशों से आयात भारी वृद्धि प्रदर्शित करते हैं, 1994-96 के संदर्भ से नहीं किया जाना है क्योंकि यह सामान्य वर्ष नहीं था। बल्कि यह 1994-95 जैसे सामान्य वर्ष के संदर्भ में किया जाना है। वर्ष 1994-95 के संदर्भ में आयातों में आंशिक गिरावट दिखाई पड़ती है और इस प्रकार 1994-95 के संदर्भ में स्वदेशी उत्पादन या उपभोग की तुलना में न तो खरब अर्थों में और ना ही सापेक्ष अर्थों में भारी वृद्धि हुई है। अतः कोई आर्थिक क्षति नहीं हुई।
- (ii) 31-3-95 के संदर्भ में, 31-8-97 को अंतिम स्टॉक में वृद्धि किसी भी प्रकार से आर्थिक क्षति नहीं दिखाती। अंतिम स्टॉक, वार स्टॉक है जो विशेष दिन में होता है और यह उतार-चढ़ाव के अधीन हो सकता है।
- (iii) 1994-95 के संदर्भ में, जॉच अवधि के दौरान स्वदेशी उद्योग की बाजार भागीदारी में लगभग 4% की गिरावट पूर्णतः अन्य देशों से आयातों के कारण आई थी। तथापि, यदि जॉच अवधि के दौरान की बाजार हिस्सेदारी की विश्लेषण 1995-96 के संदर्भ में किया जाए तो वादी कम्पनी ने 7.7% की बाजार हिस्सेदारी खो दी थी। तथापि, उक्त हानि का 5.14% आयातों की बाजार हिस्सेदारी के कारण था और बाजार हिस्सेदारी में केवल 2.56% की गिरावट ही विपयगत देशों से आयातों के कारण हो सकती है।
- (iv) एस बी आर के स्वदेशी मूल्य में गिरावट, कच्चे माल के मूल्यों में गिरावट, सीमा शुल्कों में कमी करने, उत्पादन शुल्क में कमी करने के कारण थी। इस प्रकार प्राधिकारी का यह निष्कर्ष कि मूल्यों में कमी से आर्थिक क्षति हुई है, प्रमाणित नहीं है। 31 अगस्त, 1997 में हुई हानियाँ, आरोपित पाटित आयातों के कारण नहीं हैं।
- (v) कारणात्मक संबंध पर प्राधिकारी के निष्कर्ष, इस तथ्य के कारण सही नहीं है कि यदि 1994-95 को आधार वर्ष मान कर उससे संदर्भ में मूल्यांकन किया जाए तो बाजार हिस्सेदारी में कोई गिरावट नहीं है। यदि 1995-96 को आधार बनाया जाता है तो बाजार हिस्सेदारी में 2% से कम की गिरावट, पाँच देशों से आयातों के कारण मानी जा सकती है। इसी प्रकार 97-98 में मूल्य अण्डर कटिंग, सीमा-शुल्क एवं उत्पादन शुल्क में कमी के कारण हुई दिखाई गई है। इसको देखते हुए, न तो स्वदेशी उद्योग को आर्थिक हानि हुई है। और ना ही आरोपित पाटन एवं आर्थिक क्षति के बीच कारणात्मक संबंध स्थापित हुआ है।
- (vi) वे कारक जो वादी की वास्तव में क्षति कर रहे हैं, आरोपित पाटित आयात नहीं हैं। वादी की क्षति करने वाले कारक 15 पराने पद और और अप्रचलित संयंत्र स्थान की अनुपयुक्त स्थिति, कच्चा माल प्राप्त करने का अनुपयुक्त प्रबंध और गलत वित्तीय प्रबंध हैं।
- (vii) प्रत्येक समान वस्तु के लिए क्षति निश्चयन पर अलग-अलग विचार किया जाना चाहिए। जॉच में तीन प्रकार के एस बी आर का संदर्भ है। तथापि, एस बी आर के सभी तीनों प्रकार के लिए संचयित क्षति निश्चयन किया गया है।
- (viii) एस बी आर के अन्य उत्पादक जो लघुतर क्षमता के संयंत्र चला रहे हैं, वे उन्हें कुशलतापूर्वक एवं लाभ के साथ चला रहे हैं। वादी अपना काम कुशलता-पूर्वक नहीं चला रहे हैं।
- (ix) वादी को निम्नलिखित तथ्यों के कारण क्षति नहीं हुई है :—
 - 1994-95 के संदर्भ में आयातों में आंशिक गिरावट आई है।
 - जॉच अवधि के दौरान बाजार हिस्सेदारी में गिरावट, अन्य देशों से आयातों के कारण आई है।
 - वादी की 41000 मी. टन प्रति वर्ष की संस्थापित क्षमता को वादी ने पूर्व में कमी भी प्राप्त नहीं किया है।
 - क्षमता उपयोग और उत्पाद स्थिर रहा है।
 - वर्ष 1995-96 की तुलना में, जॉच अवधि के दौरान बिक्रियों की आंशिक मात्रा उच्चतर रही है। बिक्रियाँ, मांग और वादी की बाजार हिस्सेदारी के कारण क्षति नहीं हुई है।
 - माल सूची ज्यादा नहीं है।
 - रोजगार में घटत अधिक नहीं है।
 - यदि वादी के लाभ तथा हानि के आँकड़े सही हैं तो लाभ में कोई गिरावट नहीं आई है।
 - वादी नए संयंत्र को पिछले पाँच वर्षों में चालू करने में असमर्थ रहा है। पिछले छः महीनों से उनका संयंत्र दोषपूर्ण ढंग से चल रहा है और सप्लाईयों में बाधा आती रही है।
 - पाटन तथा क्षति के बीच कारणात्मक संबंध स्थापित नहीं हुआ है।

प्राधिकारी द्वारा जाँच

21. प्राधिकारी नोट करता है कि अनेक तर्क यह दर्शाते हुए किए गए हैं कि क्षति का एक विशेष मापक, स्वदेशी उद्योग को क्षति होना नहीं बताता और इसलिए स्वदेशी उद्योग को क्षति नहीं हुई है। प्राधिकारी का, पहले जारी की गई अनेक पाटन रोधी अधिसूचनाओं में विचार रहा है तथा इस मामले में भी नोट करता है कि, यह आवश्यक नहीं है कि स्वदेशी उद्योग को क्षति के मापक, स्वदेशी उद्योग पर पाटित आयात की जाँच में उद्योग की स्थिति पर प्रभाव डालने वाले सभी आर्थिक गहलु और सूचक शामिल रहते हैं। प्राधिकारी ने आरंभिक निष्कर्षों में चर्चित के अनुसार, सभी सम्बद्ध आर्थिक कारकों को लेते हुए क्षति का संव्यवित रूप से आकलन किया है। आरंभिक निष्कर्षों में प्राधिकारी ने कारणात्मक संबंध स्थापित करते हुए कहा कि—विषयगत देशों से आयातों की मात्रा में वृद्धि से वादी की बाजार हिस्सेदारी में गिरावट आई है और स्वदेशी उत्पाद के अंडरकटिंग मूल्यों ने स्वदेशी उद्योग को अपना माल एक उचित बिक्री मूल्य से नीचे पर बेचने के लिए विवश किया। परिणामतः स्वदेशी उद्योग एक उचित बिक्री मूल्य प्राप्त करने की स्थिति में नहीं था। इस प्रकार प्राधिकारी के आरंभिक निष्कर्ष किसी एक मापक पर आधारित न हो कर क्षति के संव्यवित आकलन पर आधारित है।

22. यह तर्क दिया गया कि 95-96 एक असामान्य वर्ष था और इसलिए क्षति के निश्चयन के लिए आधार वर्ष के तौर पर नहीं लिया जाना चाहिए। तथापि, प्राधिकारी वर्षों की क्षति का आकलन करता है और यह निष्कर्ष निकालना ठीक नहीं है कि किसी एक विशेष वर्ष को आधार बना कर क्षति का निश्चयन किया जाए।

23. प्राधिकारी ने आरंभिक निष्कर्षों पर देखा है कि उद्योग ने आरोपित आयातों के कारण बाजार हिस्सेदारी खोई है यद्यपि यह तर्क दिया गया था कि बाजार हिस्सेदारी की ऐसी हानि महत्वपूर्ण नहीं है।

24. जैसा कि आरंभिक निष्कर्षों में निश्चित किया जा चुका है, स्वदेशी उद्योग को आरोपित पाटित आयातों से हुई मूल्यों की अण्डरकटिंग के कारण क्षति हुई है और परिणामतः स्वदेशी उद्योग एक उचित बिक्री मूल्य प्राप्त नहीं कर सका। जबकि यह बात मानी जाती है कि कच्चे माल के मूल्यों में कमी, सीमा-शुल्क एवं उत्पादन शुल्क को कम करने से एस बी आर का बिक्री मूल्य और उत्पादन लागत कम हो गई है, तथापि प्राधिकारी नोट करता है कि स्वदेशी उद्योग के बिक्री मूल्य में गिरावट, विशेष रूप से जाँच अवधि के अंत के समय में, लागत में गिरावट से कहीं अधिक थी और इसलिए स्वदेशी उद्योग की लाभकारिता में महत्वपूर्ण गिरावट हुई। स्वदेशी उद्योग के बिक्री मूल्य में गिरावट, विषयगत देशों के निर्यात मूल्यों में घटत का सीधा परिणाम है और इस प्रकार स्वदेशी उद्योग के मूल्यों में अंडरकटिंग थी। निर्यात मूल्यों में घटत के कारणों के संबंध में कुछ तर्क दिए गए हैं। तथापि, प्राधिकारी नोट करता है कि निर्यात मूल्य में घटत के पीछे कारणों की जाँच करने की आवश्यकता नहीं है। पाटन, क्षति तथा कारणात्मक संबंध इस जाँच की विषय वस्तु है।

25. पाटन रोधी नियमावली के अनुसरण में, अन्य बातों के साथ-साथ पाटन सीमा शुल्क उस सीमा तक लगाया जा सकता है जिस सीमा तक यह स्वदेशी उद्योग को होने वाली हानि को समाप्त करने के लिए पर्याप्त हो। अतः यदि पाटित आयात, स्वदेशी उद्योग के मूल्यों की अंडरकटिंग नहीं कर रहे हैं और ऐसे आयात ऐसे मूल्य पर हो रहे हैं जो स्वदेशी उद्योग के लिए क्षति कारक नहीं हैं, उचित बिक्री मूल्य और लैडिड मूल्य की तुलना (क्षति मार्जिन) कोई क्षति नहीं दिखाएगा और प्राधिकारी, पाटन रोधी सीमा-शुल्क लगाने की सिफारिश नहीं करेगा। उदाहरण के लिए, इस मामले में, जर्मनी और फ्रांस से निर्यात ऐसे मूल्य पर हो रहे हैं जो उचित बिक्री मूल्य से उच्चतर हैं और इसलिए प्राधिकारी को सीमा-शुल्क लगाने का कोई औचित्य नहीं मिला है। अन्य देशों के मामले में, जहाँ सीमा-शुल्क की सिफारिश की गई, प्राधिकारी ने पाया है कि निर्यात, उचित बिक्री मूल्य से नीचे के मूल्य पर किए जा रहे हैं और इसलिए क्षति मात्रिक हो गई है। सकारात्मक क्षति मार्जिन का वजूद ही स्वयं यह संकेत देता है कि स्वदेशी उद्योग उचित बिक्री मूल्य प्राप्त करने में असमर्थ रहा है और इस प्रकार मूल्यों में अण्डरकटिंग हुई है।

26. प्राधिकारी नोट करता है कि यह तर्क दिए गए हैं कि अन्य कारक भी हैं जो स्वदेशी उद्योग को क्षति पहुँचा रहे हैं, जैसे पुराने पड़ गए और अप्रचलित संयंत्र, संयंत्र स्थापना की अनुपयुक्तता, अनुपयुक्त कच्चा माल/माल सूची प्रबंधन, अर्थात् एवं अनुपयुक्त वित्तीय प्रबंधन आदि। प्राधिकारी नोट करता है कि स्वदेशी उद्योग को क्षति पर अपने प्रभाव का किसी भी कारक का परिमाणन नहीं किया गया है। जैसा कि आरंभिक निष्कर्षों में बताया गया है, स्वदेशी उद्योग की क्षति को समाप्त करने के लिए आवश्यक पाटन रोधी सीमा-शुल्क की सीमा को निश्चित करते समय प्राधिकारी ने, स्वदेशी उद्योग के लिए क्षमता के उपयोग के अधिकतम स्तर पर उत्पादन की अधिकतम लागत पर विचार करते हुए, स्वदेशी उद्योग के लिए भारत में एस बी आर के उचित बिक्री मूल्य पर धोरण किया है। इस प्रकार प्राधिकारी ने इस बात को नहीं होने दिया कि स्वदेशी उद्योग की अकुशलता का परिणाम उपभोक्ता भुगतें।

27. प्रत्येक समान वस्तु के लिए अलग-अलग क्षति के निर्धारण के संबंध में प्राधिकारी ने आरंभिक निष्कर्षों में पहले ही विचार व्यक्त किया है कि यद्यपि एस बी आर में विभिन्न प्रकारों की विशेषताएँ, प्रयोग आदि भिन्न-भिन्न होते हैं, किन्तु अनेक संसाधन हैं जो समान उपस्कर और सुविधाओं का प्रयोग करते हैं। इस तथ्य को देखते हुए कि उत्पादन पद्धति और उत्पादन क्षमताएँ विभिन्न अनुपातों में परस्पर व्यापन करते हैं, एस बी आर के प्रत्येक प्रकार के लिए अलग-अलग स्वदेशी उद्योग को हानि का हिसाब लगाना न तो उचित है और ना ही संभव। अतः प्राधिकारी, नियमों के अनुलग्नक II के पैरा 6 के अनुसार, एस बी आर के सभी प्रकारों के लिए संव्यवित रूप से क्षति का हिसाब लगाना उचित समझता है।

28. यह तर्क दिया गया है कि एस बी आर के अन्य उत्पादक, जो लघुतर क्षमता के संयंत्र चला रहे हैं वे कुशलतापूर्वक चल रहे हैं और लाभ कमा रहे हैं तथा वादी अपने कार्य को कुशलतापूर्वक नहीं चला रहे हैं। प्राधिकारी नोट करता है कि वादी, स्वदेशी उद्योग की परिभाषा को संतुष्ट करते हैं और इसलिए प्राधिकारी ने अन्य छोटे उत्पादकों के लागत पैटर्न को लिए बिना ही क्षति मार्जिन निश्चित कर दिया है। इन छोटे उत्पादकों ने न तो फाईलिंग के समय प्राधिकारी का समर्थन किया और न ही जाँच के दौरान लागत संबंधी सूचना का विवरण प्रस्तुत किया। तथापि, इस बात पर जोर दिया जाता है कि कैसे भी प्राधिकारी द्वारा क्षति का आकलन पाटनरोधी नियमों के अनुसार है।

29. उपरोक्त को देखते हुए प्राधिकारी क्षति तथा कारणात्मक संबंध पर अपने आरंभिक निष्कर्षों की पुष्टि करता है।

ज. अन्य मामले**वादी द्वारा दिये गए तर्क**

पाटनमार्जिन के होने के बावजूद कुछ श्रेणियों/देशों के लिए किसी पाटनरोधी सीमाशुल्क की सिफारिश नहीं की गयी है। प्राधिकारी को वहां पर पाटनरोधी सीमाशुल्क लगाना चाहिए जहां पाटनमार्जिन निश्चित किया गया है। उदाहरण के लिए ताईवान से आयातों के मामले में एसबीआर 1700 श्रृंखला के लिए पाटनरोधी स्थापित किया गया है किन्तु पाटनरोधी सीमाशुल्क की सिफारिश नहीं की गयी है। इसी प्रकार अमरीका से 1500 श्रृंखला के आयातों के लिए किसी पाटनरोधी सीमाशुल्क की सिफारिश नहीं की गयी है। जहां कहीं भी पाटन-मार्जिनों का निश्चयन हो चुका है, वहां पाटनरोधी सीमाशुल्क लगाया जाना चाहिए किन्तु सीमाशुल्क की सिफारिश नहीं की गयी।

प्राधिकारी द्वारा जाँच

31. पाटनरोधी नियमों के अनुसार, पाटनमार्जिन से अनधिक के पाटनरोधी सीमाशुल्क लगाए जाएंगे और यह भी कि सीमाशुल्क, स्वदेशी उद्योग को हुई हानि को समाप्त करने के लिए पर्याप्त होगा। इस प्रकार पाटनरोधी सीमा शुल्क की मात्रा, पाटनमार्जिन या क्षति मार्जिन के निम्नतर पर निश्चित की जाती है। प्राधिकारी ने निर्यातकों/देशों के लिए पाटनमार्जिन एवं क्षति मार्जिन निश्चित किए थे तथा पाटनमार्जिन और क्षति मार्जिन के निम्नतर पर पाटनरोधी सीमाशुल्कों की सिफारिश की गयी थी।

प्राधिकारी ने पाया था कि कुछ मामलों में जैसा कि वादी ने ऊपर बताया है, क्षति मार्जिन नकारात्मक थे जिसका अर्थ यह है कि ऐसे देशों से लैडिंड मूल्य, वादी के लिए अक्षतिकारक थे इसलिए प्राधिकारी को पाटनरोधी सीमाशुल्क लगाने की सिफारिश करने का औचित्य नहीं मिला, यद्यपि यह पाया गया था कि ऐसे देश/निर्यातक पाटन कर रहे हैं।

वादी द्वारा दिया गया तर्क

32. पाटनरोधी सीमाशुल्क की मात्रा निम्नतर है और स्वदेशी उद्योग को हुई हानि को समाप्त करने के लिए अपर्याप्त है। प्राधिकारी द्वारा अपनाया गया आधार मूल्य, वादी द्वारा यथाप्रस्तुत उत्पादन की लागत से नीचे है।

अधिकारी द्वारा जाँच

33. वादी का तर्क सामान्य प्रकृति का है और यह तथ्यों द्वारा प्रमाणित नहीं है। पाटनरोधी नियमों के अनुसार, प्राधिकारी, पाटनमार्जिन तथा क्षति मार्जिन के निम्नतर पर पाटनरोधी सीमाशुल्क लगाने की सिफारिश करता है और प्राधिकारी ने वर्तमान मामले में वही पद्धति अपनाई है। इस प्रकार प्राधिकारी ने ऐसे सीमाशुल्कों की सिफारिश की है जो स्वदेशी उद्योग को हुई क्षति को समाप्त करने के लिए पर्याप्त है। इस तथ्य के संबंध में एक अधिकारी द्वारा अपनाया गया आधार मूल्य, वादी द्वारा प्रस्तुत उत्पादन की लागत से नीचे है, प्राधिकारी ने, स्वदेशी उद्योग की हुई हानि को समाप्त करने के लिए आवश्यक पाटनरोधी सीमाशुल्क की सीमा को सुनिश्चित करते हुए, भारत में एसबीआर के उचित बिक्री मूल्य पर भरोसा किया। इस उचित बिक्री मूल्य का हिसाब सामान्यतः स्वीकार लेखा सिद्धांतों के आधार पर, स्वदेशी उद्योग के लिए क्षमता उपभोग के अधिकतम स्तर पर उत्पादन की अधिकतम लागत पर विचार करते हुए लगाया गया है। इस प्रकार प्राधिकारी ने उचित बिक्री मूल्य सही-सही निश्चित किया है।

वादी द्वारा तर्क

34. सीमाशुल्क की मात्रा का उत्पाद के आयात मूल्य के साथ सह-संबंध नहीं है। उन मामलों में पाटनरोधी सीमाशुल्क अधिकतर होना चाहिए जहां कि मूल्य कम है ताकि स्वदेशी उद्योग को हुई क्षति समाप्त की जा सके। तथापि, जहां भी मूल्य निम्नतर है, वहां निम्नतर सीमाशुल्क की सिफारिश की गयी है।

प्राधिकारी द्वारा जाँच

35. एक विशेष देश/निर्यातक से पाटनमार्जिन एवं क्षति मार्जिन के निम्नतर पर पाटनरोधी सीमाशुल्क की सीमा तय की जाती है। इस प्रकार सीमाशुल्क की मात्रा विभिन्न देशों/निर्यातकों के उत्पादन के मामले में आयात मूल्य के साथ सह-संबंध नहीं रख सकती। इस प्रकार वादी का तर्क, पाटनरोधी नियमों के अनुसार नहीं है।

वादी द्वारा तर्क

36. प्राधिकारी को पूर्व प्रभावी नियम के प्रावधानों को लागू करना चाहिए और जाँच के आरंभ की तारीख से पाटनरोधी सीमाशुल्क लगाना चाहिए क्योंकि वर्तमान मामले में पाटन का इतिहास है।

प्राधिकारी द्वारा जाँच

37. प्राधिकारी वर्तमान मामले में पूर्व प्रभाव के प्रावधान को लागू करना आवश्यक नहीं समझता है।

वादी द्वारा तर्क

38. यूरोपियन संघ के विभिन्न देशों से आ रहे एसबीआर निर्यातों पर पाटनरोधी सीमाशुल्क लगा देना चाहिए क्योंकि यूरोपियन संघ एक कस्टम/व्यापार युनियन है तथा उन देशों के बीच कोई व्यापार बाधा नहीं है। इस वर्ष से अकेली मुद्रा स्वीकार कर लेने के बाद यह व्यावहारिक तौर पर, वस्तुओं और सेवाओं के मुक्त आवागमन के साथ एक देश के समान हो गया है।

प्राधिकारी द्वारा जाँच

39. प्राधिकारी ने देखा है कि वादी ने सामान्य मूल्य, निर्यात मूल्य आदि पर सूचना उन विशिष्ट देशों से दी है जिनके विरुद्ध प्राधिकारी ने जाँच आरंभ की थी। प्राधिकारी इस समय यूरोपियन संघ के विभिन्न देशों पर पाटनरोधी सीमाशुल्क का लगाया जाना उचित नहीं समझता क्योंकि यूरोपियन संघ के अन्य देशों को अपने विरुद्ध पाटन के आरोपों का उत्तर देने के लिए अवसर नहीं दिया गया था। प्राधिकारी नोट करता है कि इस अवस्था में सभी यूरोपियन संघ के देशों पर पाटन रोधी सीमाशुल्क लगाना, जाँच के दायरे को बढ़ाना होगा जो इस मामले में नियमों के अनुसार नहीं है।

वादी द्वारा दिया गया तर्क

40. 1900 श्रृंखला के उत्पादन की लागत, 1500 लागत की श्रृंखला से हमेशा ही अधिक रही है। कुछ मामलों में 1900 श्रृंखला हेतु सिफारिश किया गया आधार मूल्य, 1500 श्रृंखला के लिए सिफारिश किये गए आधार मूल्य से कम है जिसके पुनर्आकलन की आवश्यकता है।

अधिकारी द्वारा जाँच

41. प्राधिकारी नोट करता है कि वादी का तर्क, पाटनरोधी नियमों के अनुसार नहीं है। आरंभिक निष्कर्षों के पैरा 22 के स्तंभ संख्या 5 में सिफारिश की गयी राशि, एक देश/निर्यातक के निर्यात मूल्य, पाटनमार्जिन और क्षति मार्जिन आदि को ध्यान में रखते हुए निश्चित की गयी है। अतः प्राधिकारी का विचार है कि वादी के उपरोक्त तर्क में म्याससंदर्भित राशियों का हिसाब सही लगाया गया है और उनका हिसाब दोबारा लगाने की आवश्यकता नहीं है।

वादी द्वारा तर्क

42. उत्पाद की मूलता, उत्पादन या निर्यात के देश की परवाह किये बिना वहाँ के निर्यातक या उत्पादक द्वारा पाटित पाए गए उत्पाद के निर्यात पर, जिसमें इसके संयुक्त उपक्रमों, अनुपंगियों या सम्बद्ध निर्यातकों द्वारा किए गए निर्यात भी शामिल हों, पाटनरोधी सीमाशुल्क लगाया जाना चाहिए।

प्राधिकारी द्वारा जाँच

43. पाटनरोधी जाँच निर्यातक/देश निर्दिष्ट हैं और इसलिए प्राधिकारी का मत है कि तर्क कानून सम्मत नहीं है।

आयातक/निर्यातक द्वारा जाँच

44. कम्पनी की घोर वित्तीय कमी को देखते हुए मैसर्स सिंथेटिक्स एंड कैमिकल्स लिमिटेड (एस एंड सीएल) ने एस बी आर का उत्पादन पूरी तरह रोक दिया है। इस प्रकार पाटनरोधी सीमाशुल्क लगाने से न तो एस एंड सी एल को सहायता मिलेगी, न ही आयातक को और जिसका परिणाम अर्थव्यवस्था पर अनावश्यक भार होगा। अतः प्राधिकारी को पाटनरोधी सीमाशुल्क वापिस ले लेना चाहिए।

प्राधिकारी द्वारा जाँच

45. वर्तमान मामले में प्राधिकारी ने पाटनरोधी नियमों के अनुसार जाँच की है। और भी, व्यवहार के अनुसार प्राधिकारी उन कारकों पर विचार नहीं करता जो जाँच की अवधि के बाद से सम्बद्ध हैं।

आयातक/निर्यातक द्वारा तर्क

46. पाटनमार्जिन के वजूद के बावजूद प्राधिकारी ने कुछ वर्गों/देशों के लिए पाटनरोधी सीमाशुल्क की सिफारिश नहीं की है क्योंकि इन देशों/वर्गों से निर्यातों का लैंडिड मूल्य, एस एंड सी एल के लिए निश्चित किये गए उचित बिक्री मूल्य के बराबर या उससे अधिक था। परिणामस्वरूप इन देशों/वर्गों के आयातों से कोई आर्थिक क्षति नहीं हो सकती थी। इस प्रकार इस संबंध में किसी परिवर्तन की जरूरत नहीं है।

प्राधिकारी द्वारा जाँच

47. प्राधिकारी इस तर्क के साथ सहमत है कि जहाँ कहीं भी उचित बिक्री मूल्य लैंडिड मूल्यों से अधिक हैं, ऐसे आयातों से वादी को कोई आर्थिक क्षति नहीं हो सकती थी।

आयातक/निर्यातक द्वारा दिया गया तर्क

48. भारतीय रुपये को विदेशी मुद्रा में बदलने के लिए प्रयोग की जाने वाली विनिमय दर वह होनी चाहिए जो आयातित माल के लिए वित्त मंत्रालय द्वारा अधिसूचित है। और भी जाँच के लिए औसत विनिमय दर उन महीनों की विनिमय दरों का साधारण औसत होनी चाहिए जिसमें निर्यातकों ने भारत को विचाराधीन उत्पाद निर्यात किये थे।

प्राधिकारी द्वारा जाँच

49. प्राधिकारी का मानना है कि वादी ने, भारत के आर्थिक सर्वेक्षण में प्रकाशित के अनुसार जाँच अवधि के दौरान विनिमय दरें दी हैं जिन पर प्राधिकारी ने विश्वास किया है। इस तर्क के संबंध में कि जाँच की अवधि के दौरान औसत विनिमय दर, उन महीनों की विनिमय दरों का सीधा औसत होनी चाहिए थी। जिनमें निर्यातकों ने उत्पाद का निर्यात किया था, प्राधिकारी को इसकी जानकारी नहीं है कि माल आयातक द्वारा वास्तव में कब छुड़ाया गया था और इसलिए, सुझाए गए के अनुसार विनिमय दर लागू करना उचित नहीं है।

आयातक/निर्यातक द्वारा दिया गया तर्क

50. जाँच अवधि के लिए भारत औसत सीमाशुल्क प्रत्येक निर्यातक के लिए अलग-अलग, उन महीनों के संदर्भ में निश्चित की जानी चाहिए जिनमें इनका भारत को निर्यात हुआ था।

प्राधिकारी द्वारा जाँच

51. लैंडिड मूल्य के निश्चयन के प्रयोजन के लिए जाँच अवधि हेतु भारत औसत सीमाशुल्क लेना प्राधिकारी का व्यवहार रहा है और भी, जब भी प्राधिकारी को निर्यातक द्वारा माल की बिक्री की तारीख/महीने के बारे में सूचना दी गयी है, यह ज्ञात नहीं है कि आयातक द्वारा माल वास्तव में कब छुड़ाए गए थे। इसलिए भारत को हुए निर्यात के महीने के संदर्भ में भारत औसत सीमाशुल्क का हिमाख लगाने से गुमराह करने वाले परिणाम प्राप्त हो सकते हैं और इसलिए, सुझाए गए के अनुसार भारत औसत सीमाशुल्क लगाना उचित नहीं होगा।

आयातक/निर्यातक द्वारा दिया गया तर्क

52. प्राकृतिक न्याय से इंकार किया गया है क्योंकि ये निष्कर्ष, हितबद्ध पार्टियों का उपलब्ध नहीं कराया गया सामग्री पर आधारित हैं जिनसे वे अपने आप को बचाने के लिए प्रतिवाद नहीं कर सके, क्योंकि अनेक सूचनाएं गोपनीय मानी गयी हैं।

प्राधिकारी द्वारा जाँच

53. पाटनरोधी नियमावली के अनुसार प्राधिकारी ने एक सार्वजनिक फाईल रखी थी जो किसी भी हितबद्ध पार्टी द्वारा देखने के लिए जाँच की अवधि के दौरान खुली रखी गयी थी। फाईल में सभी हितबद्ध पार्टियों द्वारा अगोपनीय आधार पर दी गयी सूचनाएं थीं। पाटनरोधी नियमावली के अनुसार किसी हितबद्ध पार्टी द्वारा गोपनीय आधार पर दी गयी सूचना और अधिकारी द्वारा उसे गोपनीय माने जाने पर, उसे अन्य हितबद्ध पार्टियों को प्रकट नहीं किया जाता है। इस प्रकार यह तर्क तथ्यतः गलत है। प्राधिकारी द्वारा गोपनीय मानी गयी सूचना, पाटनरोधी नियमावली के अनुसार है।

आयातक/निर्यातक द्वारा दिया गया तर्क

54. यह आश्चर्यजनक और अनुचित है कि एस बी आर के अकेले एकाधिकारी सप्लायर के कहने पर पाटनरोधी तथा संबद्ध सीमाशुल्क महानिदेशालय ने, एस बी आर के सैकड़ों उपभोक्ताओं के वास्तविक हित को पूरी तरह अनदेखा करते हुए एस बी आर आयातों पर पाटनरोधी सीमाशुल्क लगाने की सिफारिश की है।

प्राधिकारी द्वारा जाँच

55. यह तर्क सामान्य प्रकृति का है। प्राधिकारी ने वर्तमान मामले में पाटनरोधी नियमों के अनुसार जाँच की है।

आयातक/निर्यातक द्वारा दिया गया तर्क

56. वादी, देश में उद्योग की समस्त मांग को पूरा करने की स्थिति में नहीं है। पाटनरोधी सीमाशुल्क को बढ़ाने के लिए सरकार से उनका अनुरोध, उनके उत्पाद का मूल्य बढ़ाने की एक कोशिश है।

प्राधिकारी द्वारा जाँच

57. यह एक स्वीकार की गयी स्थिति है कि वादी देश में उद्योग की समस्त मांग को पूरा करने की स्थिति में नहीं है और इसे आरंभिक निष्कर्षों में पर्याप्ततः निपटाया गया है यह तर्क कि वादी का सरकार से पाटनरोधी सीमाशुल्क हेतु अनुरोध, उत्पाद मूल्य को बढ़ाने की एक कोशिश है, सामान्य प्रकृति का है। यदि वादी मूल्य बढ़ाता है, जैसा कि आयातकों द्वारा आरोपित है या उन्हें भय है, तो कोई भी हितबद्ध पार्टी पाटनरोधी नियमों के अनुसार समीक्षा के लिए आवेदन कर सकती है ताकि स्वदेशी उद्योग को क्षति, यदि कोई हो, का पुनर्आकलन किया जा सके।

आयातक/निर्यातक द्वारा दिया गया तर्क

58. वादी द्वारा दी गयी याचिका या तो झूठ है या गुमराह करने वाली है या तथ्यतः गलत है या उपभोक्ता उद्योग के हित का बिलकुल ध्यान न रखते हुए वास्तविक तथ्यों को दबाया गया है। ऊंचे मूल्य पर एस बी आर की अनुपलब्धता या उपलब्धता से कर्मी बेरोजगार हो जाएंगे। वादी का यह दावा कि वे भारत में एस बी आर की कुल आवश्यकता का उत्पादन करने में सक्षम हैं, सत्य से परे है।

प्राधिकारी द्वारा जाँच

59. यह तर्क सामान्य प्रकृति का है और तथ्यों द्वारा प्रमाणित नहीं है। वर्तमान मामले में प्राधिकारी ने पाटनरोधी नियमावली के अनुसार जाँच की है।

आयातक/निर्यातक द्वारा दिया गया तर्क

60. पाटनरोधी सीमाशुल्क, पाटनमर्जिन से अधिक नहीं होना चाहिए तथापि, आरंभिक निष्कर्षों में यह कहा गया है कि यदि लैंडिड मूल्य और उचित बिक्री मूल्य के बीच का अंतर, पाटन सीमाशुल्क से उच्चतर है तो लगाए जाने वाला सीमा शुल्क, अंतर वाला आंकड़ा होगा, जो नियमों के विपरीत है।

प्राधिकारी द्वारा जाँच

61. प्राधिकारी मानता है कि सीमाशुल्कों की सिफारिश पाटनरोधी नियमों के अनुसार की गयी है। प्राधिकारी ने अन्य अनेक पाटनरोधी जाँचों में भी इसी प्रकार पाटनरोधी सीमाशुल्कों की सिफारिश की है जो सरकार द्वारा स्वीकार कर ली गयी हैं। इस प्रकार वर्तमान मामले में पाटनरोधी सीमाशुल्कों का लगाया जाना, पाटनरोधी नियमों के विपरीत नहीं है।

आयातक/निर्यातक द्वारा दिया गया तर्क

62. कुछ निर्यातकों ने कहा है कि उन्होंने जाँच की अवधि के दौरान भारत को एस बी आर का निर्यात नहीं किया है और इसलिए उन्हें पाटनरोधी सीमाशुल्क के विचार क्षेत्र से निकाल देना चाहिए।

प्राधिकारी द्वारा जाँच

63. प्राधिकारी का मानना है कि ऐसे निर्यातक, पाटनरोधी नियमों के अनुसार नयी शिपर समीक्षा के लिए आवेदन कर सकते हैं।

आयातक/निर्यातक द्वारा दिया गया तर्क

64. प्राधिकारी ने अन्वय प्रयोक्ता उद्योग के हित पर विचार नहीं किया है। पाटनरोधी सीमाशुल्क के लिए कोई भी लेवी, उपभोक्ता उद्योग के हित में नहीं होगी और उद्योग के ढाँचे को अपूर्णनीय क्षति पहुँचाएगी।

प्राधिकारी द्वारा जाँच

65. यह तर्क सामान्य प्रकृति का है। प्राधिकारी ने इस मामले में जाँच, पाटनरोधी नियमों के अनुसार की है।

आयातक/निर्यातक द्वारा दिया गया तर्क

66. आरंभिक निष्कर्ष स्पष्ट नहीं है और बातों का क्रम नहीं बनाते क्योंकि अनेक उठाए मुद्दे प्राधिकारी द्वारा तय नहीं किये गए हैं। ये निष्कर्ष, कस्टम टेरिफ अधिनियम (1955 में यथासंशोधित), 1975 की धारा 9ए (1) के अन्तर्गत प्राधिकारी के अधिकार क्षेत्र के बाहर हैं।

प्राधिकारी द्वारा जाँच

67. प्राधिकारी नोट करता है कि विचाराधीन उत्पाद पर बातों का क्रम, समान वस्तु, स्वदेशी उद्योग, पाटन तथा पाटन मार्जिन, क्षति, कारणात्मक संबंध आदि दिया गया है। प्राधिकारी मानता है कि इसने उन सभी तर्कों और उठाए गए मुद्दों पर विचार कर लिया है जो पाटनरोधी नियमों के अनुसार पाटनरोधी शुल्कों के निश्चयन को प्रभावी कर सकते हैं। प्राधिकारी इस तर्क के साथ सहमत नहीं है कि निष्कर्ष, कस्टम टेरिफ अधिनियम (1995 में यथासंशोधित), 1975 की धारा 9ए (1) के अन्तर्गत प्राधिकारी के अधिकार क्षेत्र के बाहर हैं।

आयातक/निर्यातक द्वारा दिया गया तर्क

68. लैंडिङ मूल्य, जो संदर्भ मूल्यों को निश्चित करता है, लैंडिंग खर्च के लिए सी आई एफ मूल्य के केवल एक प्रतिशत को जोड़कर निश्चित किया जाना चाहिए। तीन प्रतिशत चार्ज करने का वर्तमान चलन गलत प्रतीत होता है क्योंकि भारत में सभी सीमाशुल्क गृह, समाकलनीय मूल्य निश्चित करने के लिए सी आई एफ के एक प्रतिशत की एक समान दर लागू करते हैं। प्राधिकारी ने ई पी डी एम मामले में केवल एक प्रतिशत का प्रयोग किया था और इसलिए संदर्भ मूल्य में संशोधन किया जाना चाहिए।

प्राधिकारी द्वारा जाँच

69. वास्तविक लैंडिंग तथा हैंडलिंग प्रभारों पर किसी भी हितबद्ध पार्टी ने सूचना नहीं दी है और इसलिए प्राधिकारी, लैंडिङ मूल्य का निश्चय करते हुए लैंडिंग प्रभारों के लिए एक प्रतिशत तथा हैंडलिंग प्रभारों के लिए दो प्रतिशत जोड़ने के सतत व्यवहार का अनुसरण कर रहा है।

आयातक/निर्यातक द्वारा दिया गया तर्क

70. आरंभिक निष्कर्षों के पैरा 22 के स्तम्भ 5 में संदर्भ मूल्य में या तो पाटन मार्जिन या क्षति मार्जिन, जो भी निम्नतर है, शामिल हैं। अतः स्तम्भ 6 में क्षति मार्जिन या पाटन मार्जिन के निम्नतर का न्यूनतम पाटनरोधी सीमाशुल्क के तौर पर संकेत, दोगुना पाटनरोधी सीमाशुल्क होता है।

प्राधिकारी द्वारा जाँच

71. आरंभिक निष्कर्ष अधिसूचना में प्राधिकारी ने कहा था कि पाटनरोधी सीमाशुल्क स्तम्भ 6 में दी गयी राशि का होगा बशर्ते सीमाशुल्क, स्तम्भ 5 में दी गयी राशियों एवं प्रतिकिलोग्राम आयातों के लैंडिङ मूल्य के बीच का अंतर होगा और यह ऐसे मामले में होगा जहां ऐसा अंतर, स्तम्भ 6 में दी गयी राशियों से अधिक हो। प्राधिकारी यह नहीं मानता कि आरंभिक निष्कर्षों में सीमाशुल्क का निर्धारण, दोगुना सीमाशुल्क लगाना है। यह तर्क तथ्यतः और विचारतः गलत है।

आयातक/निर्यातक द्वारा दिया गया तर्क

72. संदर्भ मूल्य, सीआईएफ स्तर तक ही होना चाहिए और सीमाशुल्कों के वर्तमान स्तर को नहीं लिया जाना चाहिए।

प्राधिकारी द्वारा जाँच

73. पाटनरोधी नियमों के अनुसरण में, प्राधिकारी को ऐसी राशि का निश्चय करना चाहिए जो स्वदेशी उद्योग को हुई क्षति को पूरा करने के लिए पर्याप्त हो। ऐसी राशि का हिसाब तभी किया जा सकता है जबकि जाँच की अवधि के दौरान वास्तविक लैंडिङ मूल्य का हिसाब लगाते हुए, सीमाशुल्कों

की वर्तमान दरों को हिसाब में लिया जाता है। अतः यह आवश्यक है कि स्वदेशी उद्योग को क्षति का निश्चय करते हुए, सीमाशुल्कों की वर्तमान दर को हिसाब में लिया जाए क्योंकि स्वदेशी उद्योग को क्षति उस मूल्य से है जिस पर आयातित माल, स्वदेशी बाजार में उपलब्ध हैं। अतः प्राधिकारी आरंभिक निष्कर्षों के स्तम्भ 5 में दी गयी राशि को सीआईएफ स्तर पर निश्चित करना उचित नहीं समझता।

आयातक/निर्यातक द्वारा दिया गया तर्क

74. प्राधिकारी ने जर्मनी और फ्रांस पर पाटनरोधी सीमाशुल्क नहीं लगाया है। फ्रांस और जर्मनी से अन्य निर्यातक भी हैं जिन्होंने सहयोग नहीं दिया है और उन्हें असहयोग का लाभ उठाने नहीं देना चाहिए क्योंकि असहयोगी निर्यातकों पर कोई सीमाशुल्क प्रस्तावित नहीं है। प्राधिकारी को जर्मनी और फ्रांस से असहयोगी निर्यातक के लिए संदर्भ मूल्य सूचित करना चाहिए।

प्राधिकारी द्वारा जाँच

75. प्राधिकारी मानता है कि जाँच की अवधि के दौरान जर्मनी और फ्रांस से निर्यातों के मामले में लैंडिड मूल्य, स्वदेशी उद्योग के उचित बिक्री मूल्य की तुलना में काफी ऊँचे हैं और इस प्रकार जर्मनी और फ्रांस से ऐसे आयातों पर पाटनरोधी सीमाशुल्क लगाने की आवश्यकता नहीं है। किसी भी हितबद्ध पार्टी द्वारा यह नहीं दिखाया गया है कि जर्मनी और फ्रांस से किसी भी निर्यातक का निर्यात मूल्य ऐसा है जिससे स्वदेशी उद्योग को हानि हो सके और जिस पर पाटनरोधी सीमाशुल्क लगाने की आवश्यकता हो। इन परिस्थितियों में प्राधिकारी यह नहीं पाता है कि जर्मनी फ्रांस से निर्यात, स्वदेशी उद्योग की क्षति कर रहे हैं।

आयातक/निर्यातक द्वारा दिया गया तर्क

76. मैसर्स जे एस आर, जो जापान के एक निर्यातक हैं, ने तर्क दिया है कि उन्होंने भारत को एसबीआर का निर्यात सीधे नहीं किया है बल्कि विभिन्न व्यापार संगठनों जैसे जेटीसी और मित्सुई के माध्यम से किया है। प्राधिकारी को जेएसआर-मित्सुई तथा जेएसआर-जेटीसी के जोड़ों के लिए संदर्भ मूल्य बताना चाहिए। उत्पादक-निर्यातक के जोड़े के लिए संयुक्त दर बताने की पद्धति अमरीका में प्रचलित है।

प्राधिकारी द्वारा जाँच

77. केवल उत्पादकों का आकलन करना और तदनुसार सीमाशुल्क की सिफारिश करना प्राधिकारी का सतत व्यवहार रहा है। जब तक आयातक सीमाशुल्क प्राधिकारी को संतुष्ट करने योग्य है कि माल का उत्पादन एक विशिष्ट उत्पादक द्वारा किया गया है जिसका नाम इस अधिसूचना में सीमाशुल्क की राशि बताते हुए इंगित किया गया है, सीमाशुल्क प्राधिकारी तदनुसार पाटनरोधी सीमाशुल्क लगाएंगे। और भी, एक ऐसे व्यापारी का सामान्य मूल्य निश्चित करना संभव नहीं है जो किसी भी उत्पादक के माल का निर्यात कर सकता है। अतः व्यापारियों पर पाटनरोधी सीमाशुल्क लगाना और उसका मॉनीटर करना व्यावहारिक नहीं है। अतः प्राधिकारी उत्पादक और व्यापारी के जोड़े के लिए संदर्भ मूल्य बताना उचित नहीं समझता।

निर्यातक द्वारा दिया गया तर्क

78. कोरिया के निर्यातक ने तर्क दिया है कि उनका पाटनमार्जिन और निर्यात मूल्य कोरियन मुद्रा में निश्चित किया जाए।

प्राधिकारी द्वारा जाँच

79. भारतीय रुपयों में पाटनरोधी सीमा शुल्क की सिफारिश करना प्राधिकारी का सतत व्यवहार रहा है और इसलिए प्राधिकारी, विदेशी मुद्रा में सीमाशुल्कों की सिफारिश करना उचित नहीं समझता।

३. अंतिम निष्कर्ष

80. उपरोक्त पर विचार करने के बाद प्राधिकारी का निष्कर्ष है कि :—

- (क) जापान, कोरिया आर. पी., टर्की, ताईवान, अमरीका, जर्मनी और फ्रांस से भारत को एसबीआर के निर्यात, इसके सामान्य मूल से सीधे पर किये गए हैं जिसके परिणामस्वरूप एसबीआर का पाटन हुआ है;
- (ख) स्वदेशी उद्योग को आर्थिक क्षति हुई है;
- (ग) पाटन तथा क्षति के बीच कारणात्मक संबंध स्थापित हो गया है।

81. प्राधिकारी, पाटनरोधी सीमाशुल्क लगाने के संबंध में आरंभिक निष्कर्षों की पुष्टि करता है और जापान, कोरिया, आर. पी. टर्की, ताईवान, अमरीका मूल के या वहाँ से निर्यातित विचाराधीन उत्पाद से संबंधित पैराग्राफ के अंतर्गत यथाविनिर्दिष्ट, कस्टम टैरिफ अधिनियम के कस्टम उपशीर्ष नम्बर 4002.19 के अन्तर्गत आने वाले एसबीआर के आयातों पर निश्चित पाटनरोधी सीमाशुल्क लगाने की सिफारिश करता है। फ्रांस और जर्मनी से निर्यातों या अमरीका से 1500 शृंखला, ताईवान से 1700 शृंखला और टर्की से 1700 शृंखला के निर्यातों पर किसी पाटनरोधी सीमाशुल्क की सिफारिश नहीं की गयी है क्योंकि ऐसे निर्यातकों को स्वदेशी उद्योग की क्षति करने वाला नहीं पाया गया था। पाटनरोधी सीमाशुल्क, स्तम्भ 6 में दी गयी राशियों का होगा बशर्ते सीमाशुल्क, स्तम्भ 5 में दी गयी राशियों और प्रति किलोग्राम आयातों के लैंडिड मूल्य का अंतर होगा, यदि ऐसा अंतर, स्तम्भ 6 में दी गयी राशियों से अधिक का है।

क्रम संख्या	देश	उत्पादक/निर्यातक	वर्ग	राशि (रु. प्र. कि. ग्रा.)	राशि (रु. प्र. कि. ग्रा.)
1	2	3	4	5	6
1.	अमरीका	सभी निर्यातक	1500 शृंखला	—	—
			1700 शृंखला	48.20	3.48
			1900 शृंखला	62.16	6.77
2.	ताईवान	ताईवान सिंथेटिक	1500 शृंखला	57.33	2.21
		रबड़ कार्पोरेशन	1700 शृंखला	—	—
			1900 शृंखला	57.90	3.20
		अन्य	1500 शृंखला	58.33	3.20
			1700 शृंखला	—	—
			1900 शृंखला	57.190	3.20
3.	टर्की	पैटकिम पैट्रोकिम्या	1500 शृंखला	57.50	8.26
			1700 शृंखला	—	—
			1900 शृंखला	62.16	9.72
		अन्य	1500 शृंखला	59.82	10.57
			1700 शृंखला	—	—
			1900 शृंखला	62.16	9.72
4.	कोरिया	कोरिया कुम्हो	1500 शृंखला	56.10	4.95
			1700 शृंखला	48.20	1.08
			1900 शृंखला	59.15	7.26
		अन्य निर्यातक	1500 शृंखला	58.42	7.26
			1700 शृंखला	48.20	1.08
			1900 शृंखला	59.15	7.26
5.	जापान	जेएसआर कार्पो.	1500 शृंखला	59.82	3.71
			1700 शृंखला	48.20	0.92
			1900 शृंखला	62.16	5.59
		अन्य	1500 शृंखला	59.82	3.71
			1700 शृंखला	48.20	0.92
			1900 शृंखला	62.16	5.59

82. प्रयोजन के लिए आयातकों का लैंडिड मूल्य, कस्टम्स अधिनियम, 1962 के अन्तर्गत कस्टम्स द्वारा यथानिर्धारित आकलित मूल्य होगा और, कस्टम्स टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 3, 3(ए), 8बी, 9 तथा 9ए के अन्तर्गत लगाए गए सीमाशुल्कों के अलावा सभी सीमाशुल्क इसमें शामिल होंगे।

83. उपरोक्त के अधीन रहते हुए प्राधिकारी तारीख 21-1-1999 के आरंभिक निष्कर्षों की पुष्टि करता है।

84. इस आदेश के विरुद्ध अपील, पहले के अधिनियम के अनुसार कस्टम्स, एक्साइज तथा गोल्ड (नियंत्रण) अपीलीय ट्रिब्यूनल के समक्ष की जाएगी।

रति विनय झा, नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE

New Delhi, the 2nd June, 1999

FINAL FINDINGS

Subject : Anti-dumping investigation concerning import of Styrene Butadiene Rubber from Japan, Korea RP, Turkey, Taiwan, USA, Germany and France – Final Findings.

No. 30/1/97-ADD.—Having regard to the Customs Tariff Act, 1975, as amended in 1995 and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for determination of injury) Rules, 1995 thereof.

A PROCEDURE:

1. The procedure described below has been followed subsequent to the preliminary findings:

(a) The Designated Authority (hereinafter also referred to as the Authority) notified preliminary findings vide notification dated the 21.01.99 with regard to anti-dumping investigations concerning import of Styrene Butadiene Rubber (SBR) from Japan, Korea RP, Turkey, Taiwan, USA, Germany and France and requested the interested parties to make their views known in writing within forty days from the date of its publication;

(b) The Authority forwarded a copy of the preliminary findings to the known interested parties, who were requested to furnish their views, if any, on the preliminary findings within forty days of the date of the letter;

(c) The Authority also forwarded a copy of the preliminary findings to the Embassy of the Japan, Korea RP, Turkey, Taiwan, USA, Germany and France in New Delhi with a request that the exporters and other interested parties may be advised to furnish their views on the preliminary findings;

(d) The Authority had provided an opportunity to all interested parties to present their views orally on 10.11.1998 before the preliminary findings notification was issued. After the preliminary findings notification, the Authority provided an opportunity to exporters on 25.2.99 and to petitioner, importers and other interested parties, on 26.2.99 to present their views orally. All parties presenting views orally were requested to file written submissions of the views expressed orally. The parties were advised to collect copies of the views expressed by the opposing parties and offer rebuttals, if any ;

- (e) The Authority made available the public file to all interested parties containing non-confidential version of all evidence submitted and arguments made by various interested parties. All parties who made requests for inspection, in writing, were allowed to inspect the public file ;
- (f) Arguments raised by the interested parties before announcing the preliminary findings, which have been brought out in the preliminary findings notified have not been repeated herein for sake of brevity. However, the arguments raised by the interested parties have been appropriately dealt with in the preliminary findings and/or these findings;
- (g) In accordance with Rule 16 of the Rules Supra, the essential facts/basis considered for these findings were disclosed to known interested parties and comments received on same have been duly considered in these findings;
- (h) The Authority had sought extension from Government by two months to complete the investigation, which was allowed by the Central Government. The investigation has been completed within the extended period.
- (i) ***In this notification represents information furnished by an interested party on confidential basis and so considered by the Authority under the Rules.

B. INITIATION OF INVESTIGATION:

2. The Authority issued a Public notice dated 7th April, 1998, published in the Gazette of India, Extra Ordinary, initiating anti-dumping investigations concerning imports of SBR classified under custom code 4002.19 of schedule I of the Customs Tariff Act 1975 originating in or exported from Japan, Korea RP, Turkey, Taiwan, USA, Germany and France.

Argument by Importer

3. The petitioner had failed to provide evidence on normal value and relied on many presumptions and assumptions. Application submitted by the petitioner was deficient since there was no evidence of normal value of SBR in respect of Korea RP and petitioner had failed to produce prima-facie evidence of dumping from Korea RP. The Authority had initiated the investigation without examining the accuracy and adequacy of the evidence provided to the Authority by petitioner. Hence the initiation of the investigation is void ab-initio.

Examination by Authority:

4. It is evident from the petition filed by the petitioner that information on normal value and export price were provided in respect of all countries. The basis of calculation of such value/price were also indicated in the petition. The petitioner is also entitled to rely upon the secondary information which are publically available. The rules also permit the construction of normal value and export price in the absence of exact information. Therefore, during the course of investigation, all interested parties are provided with opportunities to comment upon the information provided by petitioner which are duly considered by Authority.

It is incorrect to say that Authority had initiated the investigation without examining the accuracy and adequacy of information. In the initiation notification, the Authority had clearly provided the necessary information on Like Articles, Domestic Industry, Dumping ,Injury and Causal link. It is also incorrect to say that petitioner had failed to provide prima-facie evidence on dumping. The petitioner had indicated in the petition as to how the normal value , export price and dumping margin had been claimed. Since the petitioner had furnished the necessary information to initiate the investigation, the Authority on being satisfied, had initiated the investigation in accordance with Rules and therefore the Authority hold that investigation initiated is valid and is not void ab-initio.

C. PRODUCT UNDER CONSIDERATION:

5. Product involved in the present investigation is Styrene Butadiene Rubber (SBR) originating in or exported from the subject countries classified under custom sub heading 4002.19 of the Custom Tariff Act, which has been explained in para 5 of the preliminary findings dated 21st January,1999. The Authority had, inter-alia held at para 5 of the preliminary findings that product under consideration is SBR of 1500 series, 1700 series and 1900 series under Customs sub heading 4002.19 of the Custom Tariff Act.

Argument by petitioner

6. (i) SBR 1900 series is also being imported under chapter 39 of the Customs Tariff and consequently the recommendation of the Authority should cover not only chapter 40 but also chapter 39, entry No. 3903.90(polymers of styrene in primary forms – other). Once the product has been identified as SBR, the anti-dumping duty is to be levied on all the imports of the product irrespective of custom code under which it is imported. The scope of the product for imposition of the duty needs to be modified. The petitioner has alleged that high Styrene Rubber of 1900 series had been imported under the trade name of KHS 68 under the Custom Code Chapter 39 as well as under chapter 40 from Korea RP.

Argument by Importer & Exporter

6.(ii) This submission of the petitioner is erroneous. Chapter 39 of the Custom Tariff specifically provides that chapter 39 does not cover Synthetic Rubber or articles thereof as defined in chapter 40. Consequently if SBR imported from these countries does not satisfy the definition of synthetic rubber (vide note 4 to chapter 40) it will cease to be synthetic rubber and may be treated as articles of plastics. SBR 1900 series, as the name itself suggests are a synthetic rubber and not an article of plastic. The exporter from Korea RP has also argued that KOSYN KHS 68 is a polymer resin falls under chapter 39 as it contains 68% Styrene and about 32% of Butadiene.

Examination by Authority

7. The Authority observes that, in the preliminary findings it was inter-alia held that product under consideration in the present investigation is Styrene Butadiene Rubber (SBR) originating in or exported from the subject countries classified under Custom sub heading 4002.19 of the Custom Tariff Act which was explained at para 5 of the preliminary findings dated 21st January, 1999. The Authority had inter-alia held that product under consideration is SBR of 1500 series, 1700 series and 1900 series under Custom -sub-heading 4002.19 of custom Tariff Act. None of the interested parties has raised any argument in this regard and therefore the Authority confirms its preliminary findings in this regard.

The Authority notes that petitioner is claiming that SBR is also being cleared under custom chapter 39 entry no. 3903.90 (polymers of styrene in primary forms) and therefore the anti-dumping duty should be imposed under this head also. On the contrary it is argued by exporter and importer that chapter 39 relates to plastic and does not cover SBR and therefore duty should not be imposed on products covered under chapter 39 entry no. 3903.90. The Authority observes that chapter 39 covers "Plastic & Articles Thereof" whereas chapter 40 covers "Rubber & Articles Thereof". Styrene Butadiene Rubber as the name suggest is a synthetic rubber and is covered under chapter 40. It is also observed that as per note no. 2(h) of chapter 39, the synthetic rubbers or articles thereof which are covered under chapter 40, do not fall under chapter 39. It is also observed that while giving the import statistics, the petitioner had submitted information in respect of custom heading No. 4002.19 only. While submitting the evidence that SBR 1900 series is also being imported under chapter 39, the Authority observes that the item cleared under chapter 39 is "Elastomer Resin KHS 68" and thus it is not under the nomenclature of "Synthetic Rubber". In view of this, the Authority does not find justification to cover item falling under sub-heading 3903.90 for the purpose of imposing anti-dumping duty.

However, the Authority agrees with the argument of the petitioner to the extent that product under consideration is Synthetic Butadiene Rubber of specified series as stated, irrespective of custom heading. The Authority thus holds that whereas it is not justified to cover all items falling under the sub heading 3903.90, for the purpose of imposing anti-dumping duty in present case the anti-dumping duty however is payable on Styrene Butadiene Rubber of specified series as stated, even if it is sought to be cleared under any other heading of the Custom Tariff Act. The Custom Authorities are at liberty and expected to classify the goods correctly, if the goods offered for clearance are not classified correctly.

D. LIKE ARTICLE:

8. The Authority notes that no argument has been made by any interested party in this regard after the preliminary findings notification was issued. Therefore the Authority confirms its preliminary findings in this regard.

E. DOMESTIC INDUSTRY:

9. The Authority notes that no argument has been made by any interested party in this regard after the preliminary findings notification was issued and therefore the Authority confirms the preliminary findings in this regard.

F. DUMPING:

10. The rules relating to dumping have already been discussed in preliminary findings. The submissions made by exporter subsequent to preliminary findings and its examination by Authority is as under :-

(i) Country-USA**Exporter – Ameripol Synpol Corpn.**

The exporter has submitted that grade 8401 falls under 1700 series but has maintained that this is not a like article to the product under consideration and they are sole producer of this grade in the world .

They have not yet submitted the costing information as observed in preliminary findings and therefore the information submitted by them on normal value can not be accepted. Therefore the Authority confirms the dumping margin of 30.55% of export price as determined in the preliminary findings.

(ii) Country : France**Exporter: Bayer**

They have not submitted any further information relating to calculation of dumping margin and therefore the Authority confirms the dumping margin of 28.20% of export price as determined in the preliminary findings.

(iii) Country: Germany**Exporter – BSL**

They have not submitted any further information relating to calculation of dumping margin and therefore the Authority confirms the dumping margin of 24.86% of export price as determined in the preliminary findings.

(iv) **Country – Taiwan**
Exporter-Taiwan Synthetic Rubber Corpn.

The exporter has not submitted any further information in respect of dumping margin calculated earlier in the preliminary findings. Further they have neither contested the methodology nor the calculation of dumping margin as determined in the preliminary findings. Therefore the Authority confirms the dumping margin at 6.68% of export price in respect of SBR 1502 grade and at 6.07% of export price in respect of SBR 1712 grade as determined in the preliminary findings.

(v) **Country- Turkey**
Exporter- Petkim holding AS

The exporter was explained the methodology of calculating the dumping margin and the figures used for the calculation at their request when they attended the public hearing on 25/2/99. Thereafter, the exporter has revised its claim on domestic price and claimed a lower dumping margin. It is claimed that inflation rate in Turkey is high which requires a price adjustment amounting upto 5-8% monthly. It is further claimed that domestic price declared in response to the questionnaire were the average of all applied prices including interest rate for credit facilities whereas interest rate in export price declared were excluded. Moreover the exports to Indian Market were made at introductory prices.

They have revised the domestic price claiming the effect of inflation and have requested that due to this their dumping margin be revised to 12.47% in respect of S 1502 grade from 28.82% determined earlier in preliminary findings and dumping margin be revised to 9 % in respect of S 1712 grade from 13.66% determined earlier in preliminary findings. However no evidence has been produced to substantiate their claims. After the disclosure statement was issued, they have further revised their claims and requested that their dumping margin be revised to 14.06% in respect of S 1502 grade and dumping margin be revised to 6.65% in respect of 1712 grades.

Examination by Authority:

The Authority observes that the exporter has revised the domestic prices as explained above after the preliminary findings were notified and after the Authority had held oral hearing with exporters. They have also revised their claim on domestic prices subsequent to issue of disclosure statement. Even during the oral hearing the exporter did not disclose that they shall be revising their domestic price for the purpose of determining the normal value. The Authority thus notes that revised information has been submitted at such a late stage that other interested parties have not got a reasonable opportunity to comment on such information. Further, the revised information has not been substantiated with evidence. Considering that the information has not been submitted in time and that they are unsubstantiated, the Authority did not consider it appropriate to verify the information and is constrained to ignore the revised information

submitted due to reasons explained above. In view of this the Authority confirms the dumping margin at 28.82% of export price in respect of SBR 1502 grade and of 13.66% of export price in respect of S 1712 grade, as determined in the preliminary findings.

(vi) **Country : Korea**
Exporter – Korea Kumho Petrochemicals Ltd.

The exporter was explained the methodology and figures used in calculating the dumping margin, as determined in the preliminary findings, during the verification which has not been disputed. In their subsequent submissions they have requested to allow the claims on account of storage, technical services, promotional travelling expenses, bad debts expenses and advertisement which were not allowed earlier while determining the normal value. During the verification, they have made claims on account of R & D expenses and donations while determining normal value and also stated that they shall be making a claim on account of “interest”, the details of which are not received so far. They have revised the amount per tonne in respect of certain claims which were allowed earlier. On the basis of their revised claim they have claimed de-minimus dumping margin.

Examination by Authority:
Normal Value :

The normal value is calculated on the basis of weighted average of domestic price. The Authority allows the adjustment on account of discount/credit interest, packing, inland freight and taxes as verified during the course of verification. The adjustment claimed on account of technical services, promotional travelling expenses, R&D expenses and advertisement is not allowed as it is not substantiated how the benefit of these expenses are being restricted to domestic market only. The adjustment on account of storage is not allowed as it is a post manufacturing expense. The adjustment on account of bad debt expenses are now allowed as the incidence of these expenses are not known at the time of sales. The adjustment on account of donation is not allowed, as it is a non-operational expense. The adjustment on account of handling is not allowed as it was not substantiated during the verification. Thus the normal value is determined at US\$ *** PMT in respect of SBR 1502 and at US\$ *** in respect of SBR 1712 grade.

Export prices:

The export price is calculated on the basis of weighted average of export sales to India. The adjustment claimed on account of discount/commission, packing, inland freight, inspection fee, overseas freight and overseas insurance are allowed as verified during the verification. The export price is determined at US\$ *** PMT in respect of SBR 1502 grade and at US\$ *** PMT in respect of SBR 1712 grade. The dumping margin is calculated at US\$ *** PMT in respect of SBR 1502 grade which is 16.82 % of export price and at US\$ *** PMT in respect of SBR 1712 grade which is 10.94 % of export price.

The authorised representative of exporter in India had requested to lift the confidentiality of information. However the exporter has still requested to maintain the confidentiality. As the exporter has not lifted the confidentiality, the Authority has considered it appropriate to treat information as confidential wherever these were claimed as confidential.

(vii) **Country: Japan**
Exporter: JSR Corpn.

The exporter was explained the methodology and figures used in calculating the dumping margin, as determined in the preliminary findings, during the verification which has not been disputed. In their subsequent submission, they have requested to allow their claim on account of extra grades produced for domestic market, which was earlier disallowed by Authority in the preliminary findings. During verification, they also claimed an adjustment on account of the fact that whereas in the export sales, the sales are through agent to whom commission is payable but in the domestic market sales are made direct to customers and hence there is a difference in the level of trade. It is claimed that commission paid in the case of export sales be equally allowed in the case of domestic sales also. They have claimed de-minimus dumping margin.

Examination by Authority
Normal Value :

The normal value is calculated on the weighted average price in the domestic market. The adjustment on account of inland freight, insurance and interest are allowed as verified during the verification. The claim on account of storage cost is not allowed as it is post-manufacturing expense. The claim on account of extra grades produced for the domestic market is based on estimates and is not actually incurred by the exporter and hence not allowed. The claim was not substantiated with evidence during verification also. The adjustment on account of commission due to difference in the level of trade is not allowed as it is on the basis of estimates and is not actually incurred by the exporter.

Export Price:

The export price is calculated on the basis of weighted average price. The claim on account of commission to Japanese Trading House, Indian agents, Inland freight, insurance, overseas freight and insurance, interest and commission are allowed as verified during the verifications. The dumping margin is determined at US\$ *** PMT in respect of 1500 grade which is 3.36 % of export price, is determined at US\$ *** PMT in respect of 1502 grade which is 17.32 % of export price and is determined at US\$ *** PMT in respect of S1712 grade which is 7.64% of export price.

11. Dumping margin in respect of non-cooperating exporters and other issues on dumping have been dealt with in the subsequent paragraphs.

Argument by petitioner

12. The Authority has recommended uniform duty on all the exporters including the non-co-operating exporters from a country based on the responses and data submitted by one or two exporters only. Some of the exporters might be dumping with higher dumping margin as claimed by the petitioner. Therefore anti-dumping duty equivalent to the dumping margin established by the petitioner in their petition be imposed on all exporters who have not responded or are non-co operative.

Examination by Authority

13. In respect of non co-operative exporters from subject countries who has not responded to questionnaire the Authority had determined dumping margin at the highest dumping margin determined for the co-operative exporters from each country in the preliminary findings.. Thus the dumping margin as percentage of ex-factory export price for non-cooperating exporters from Taiwan was determined at 6.68%, from Turkey 28.82%, from Korea at 11.66% and from Japan at 17.32%.

The Authority notes that not only the petitioner but even the co-operating exporters are of the opinion that the non-cooperating exporters should not be benefited in any way in view of their act of non-co-operation. The Authority also holds the same view and therefore determines the dumping margin as claimed by petitioner in their petition in respect of non-cooperating exporters. Thus the dumping margin is determined at 30.55 % , 28.20% , 24.86 % , 9.21 % , 77.6% , 18.78 % , 90.79 % respectively for non-cooperating exporters from USA, France, Germany, Taiwan, Turkey, Korea RP, and Japan. However anti-dumping duty is levied as per law which provides for the lower of the dumping margin and injury margin.

Argument by petitioner

14. The adjustment claimed by exporter in determining the dumping margin appears to be high. Korean exporter and its local agent are trying to mislead the Authority by claiming baseless and incorrect adjustment. The Authority has correctly disallowed certain adjustment in preliminary findings. However claim of exporter with regard to packing and other adjustment allowed by Authority does not appear to be based on the actual expenses incurred by company.

Examination by Authority:

15. The argument of petitioner is generic in nature and is not substantiated with facts and evidence. The Authority had verified the information in respect of exporter from Japan and Korea RP, to the extent considered necessary. The examination of claims have already been discussed above. The Authority holds that allowance of claim as discussed in relevant paragraphs is justified as they are based on verification of information by Authority.

Argument by petitioner

16. In a recent decision, US Govt have imposed anti-dumping duty on SBR producers from South Korea, , Brazil & Mexico. The quantum of duty imposed is at 119% of FOB value for certain producers from Korea which indicates that the quantum of anti-dumping duty being imposed needs to be substantially increased as there can not be any significant difference while computing prices by the two anti-dumping Authorities.

Examination by Authority

17. The petitioner has not substantiated its claim. The Authority has already explained its methodology for calculation of dumping margin which is not contested and is in accordance with Anti-dumping Rules. The Authority does not consider it appropriate to compare the dumping margin in respect of two different countries in the absence of necessary details regarding the period of investigation, product under consideration, normal value, export price etc.

18. Based on above the dumping margins are determined as under :-

Sl. No.	Country	Exporter	Grade	Dumping Margin as % of export price
1.	USA	All Exporters	All Grade	30.55
2.	France	All Exporters	All Grade	28.20
3.	Germany	All Exporters	All Grade	24.86
4.	Taiwan	(i) Taiwan Synthetic Rubber Corpn. (ii) Other Exporters	S 1502 S 1712 All Grade	6.68 6.07 9.21
5.	Turkey	(i) Petkin Petrokinya (ii) Other Exporters	S 1502 S 1712 All Grades	28.82 13.66 77.60
6.	Korea R.P.	(i) Korea Kumho (ii) Other Exporters	S 1502 S 1712 All Grade	16.82 10.94 18.78
7.	Japan	(i) JSR Corpn. (ii) Other Exporters	S 1500 S 1502 S 1712 All Grades	3.36 17.32 7.64 90.79

Note : None of the co-operative exporters have submitted information in respect of 1900 series SBR. Hence for 1900 series SBR, they shall fall under the "other exporter" category.

G. INJURY AND CAUSAL LINK:

19. The rules relating to injury and causal link has been discussed in the preliminary findings notification. Various factors which are causing injury and the establishment of causal link has also been discussed in preliminary findings.

20. The following arguments have been raised by importers/exporters/other interested parties.

(j) Determination of issue as to whether imports from subject countries showed significant increase has to be made not with reference to 95-96 which was not a normal year but with reference to a normal year like 94-95. With reference to 94-95, the imports have shown a marginal decline and thus there is no significant increase either in absolute terms or in relative terms to domestic production or consumption with reference to 94-95. Hence there is no material injury.

(ii) The increase in closing stock on 31.8.97 with reference to 31.3.95 can not at all show material injury. The closing stock is the stock held on a particular day and can be subject to wide fluctuation.

(iii) The decline of about 4% in market share of the domestic industry during the period of investigation with reference to 94-95 is entirely caused by the imports from other countries. However if the market share during the period of investigation is analysed with reference to 95-96, the Petitioner Company had lost a market share of 7.7%. However 5.14% of the said loss was because of the increase in market share of imports from other countries and only 2.56% of the decline in market share can, if at all, be attributable to the imports from the subject countries.

(iv) The fall in the domestic price of SBR are due to fall in the raw material prices, lowering of custom duties, lowering of excise duty. Thus the conclusion of the Authority that reduction in price had caused material injury is unsustainable. The losses in April-August 97 are not attributable to the allegedly dumped imports.

(v) The findings of the Authority on causal link is incorrect due to the fact that there is no decline in market share to domestic industry if evaluated with reference to 94-95 as the base year. If 95-96, is taken as the base less than 2% of the fall in the market share could only be attributed to the import from five countries. Similarly the alleged price under cutting in 97-98 has been demonstrated to have been caused by the reduction in custom duties and the reduction in excise duty. In view of this, there is neither a material injury to the domestic industry nor causal link between the alleged dumping and material injury has been established.

(vi) The factors which are actually causing injury to the petitioner are not alleged dumped imports. The factors which are causing injury to petitioner are outdated and obsolete plant, improper location of the plant site, improper arrangement for procurement of raw material and inventory management, inadequate and improper financial management.

(vii) Injury determination should be considered separately for each like product. Three type of SBR has been referred to in the investigation. However cumulative injury determination has been made for all three type of SBR.

(viii) The other producers of SBR who are operating smaller capacity plants are running efficiently and profitability. Petitioner is not managing their affairs efficiently.

(ix) The petitioner has not suffered injury due to the following facts: -

- The imports have decreased marginally w.r.t. 1994-95.
- Decline in the market share to domestic industry during the period of investigation is caused by imports from other countries.
- Installed capacity of 41000 MT p.a of the petitioner has never been achieved in the past by the petitioner.
- There is a stable production and capacity utilisation.
- There is a higher marginal-quantum of sales in period of investigation as compared to 1995-96. Sales, demand and market share of petitioner does not lead to injury.
- Other producers are running efficiently.
- Inventory is not much.
- Reduction in employment is not substantial.
- There is no decline in profit if profit and loss figures of petitioner are corrected.
- Petitioner has not been able to commission the new plant for the last five years. For last six months their plant is working very erratically and supplies are disrupted.
- Causal link between dumping & injury is not established.

Examination by Authority

21 The Authority notes that many arguments have been made showing that a particular parameter of injury does not show injury to domestic industry and hence the domestic industry has not suffered injury. The Authority has already held the view in a number of anti-dumping notifications issued earlier and also notes in the instant case that all injury parameters relating to domestic industry need not indicate injury to the domestic industry. In accordance with the Anti-dumping rules, the examination of the impact of the dumped import on the domestic industry includes an evaluation of all-relevant economic factors and indices having a bearing on the state of industry. The Authority had assessed the injury cumulatively taking into account all the relevant economic parameters as discussed in the preliminary findings. In the preliminary findings the Authority while establishing the causal link, had stated that increase in quantum of import from subject countries had resulted in decline of the market share of the petitioner and were undercutting prices of domestic product forcing the domestic industry to sell below a reasonable selling price. Resultantly the domestic industry was not in a position to recover a reasonable selling price. Thus the preliminary findings of the Authority is not based on any single parameter but is based on the cumulative assessment of injury.

22. It has been argued that 95-96 was an abnormal year and therefore should not be taken a base year for determining the injury. The Authority, however, assess the injury over the years and it may be incorrect to conclude that injury be determined keeping any particular year as a base.

23. The Authority had observed in the preliminary findings that domestic industry had lost market share due to alleged imports. The fact that domestic industry had lost market share remains undisputed although argument have been made that such loss of market share is not significant.

24. As already determined in the preliminary findings, the domestic industry has suffered injury due to price undercutting from the alleged dumped imports and consequently domestic industry was not able to recover a reasonable selling price. While it is appreciated that certain elements of cost of production and selling price of SBR has declined in view of reduction in raw material prices, lowering of custom duty and excise duty, the Authority however notes that the decline in selling price of domestic industry, particularly towards the end of investigation period was more than the reduction attributable to the decline in cost and therefore there was significant deterioration of profitability of the domestic industry. The decline in the selling price of the domestic industry is a direct consequence of reduction in export price from the subject countries and thus there was an undercutting of prices of domestic industry. Certain Arguments have been made regarding reasons for the reduction in export price. However, the Authority, notes that it is not required to examine the reasons behind reduction in export price. Dumping, injury and causal links are the subject matter of investigation.

25. In accordance with the anti-dumping rules, anti-dumping duty inter-alia, can be levied to the extent it is sufficient to remove injury to the domestic industry. Therefore in case, the alleged dumped imports are not under cutting the prices of domestic industry and such imports are taking place at a price which is not injurious to domestic industry, the comparison of reasonable selling price and landed value (injury margin) will not show any injury and Authority will not recommend imposition of anti-dumping duty. For instance, in this case the exports from Germany and France are taking place at a price which is higher than the reasonable selling price and therefore Authority had not found justification to impose duties. In the case of other countries, wherever duties have been recommended, the Authority had found that exports are taking place at a price which is below the reasonable selling price and therefore injury has been quantified. The existence of positive injury margin itself indicate that the domestic industry is not able to recover reasonable selling price and thus there is price-under cutting.

26. The Authority notes that arguments have been made that there are other factors which are causing injury to the domestic industry such as outdated and obsolete plant, improper plant location, improper raw material/inventory management, inadequate and improper financial management etc. The Authority notes that none of the factors have been quantified in terms of their impact on injury to the domestic industry. As already indicated in the preliminary findings, the Authority while ascertaining the extent of anti-dumping duty necessary to remove injury to domestic industry, relied upon reasonable selling price of SBR in India for the domestic industry, by considering the optimum cost of production at optimum level of capacity

utilisation for the domestic industry. In this way, the inefficiencies, if any, of the domestic industry are not allowed to be passed on to the consumers by the Authority.

27. With regard to separate assessment of injury for each like Article, the Authority has already observed in the preliminary findings that though the different types of SBR have different characteristics, usage etc. there are number of processes which use common equipment and facilities, In view of the fact that production processes as well as the production capacities overlap each other in varying proportions, it would neither be appropriate nor feasible to assess the injury to domestic industry for each individual type of SBR. The Authority, therefore in accordance with para 6 of Annexure II to the rules, consider it appropriate to assess the injury for all types of SBR cumulatively.

28. It is argued that other producer of SBR who are operating smaller capacity plant are running efficiently and earning profit and petitioner is not managing their affairs efficiently. The Authority notes, that petitioner satisfied the definition of domestic industry and therefore Authority has determined the injury margin without taking the cost pattern of other small producers. These small producers had neither supported the petition at the time of filing nor submitted detailed costing information during the course of investigation. It may however be reiterated that even otherwise, the assessment of injury by the Authority is in accordance with the anti-dumping rules.

29. In view of above, the Authority confirms its preliminary findings on injury and causal link.

H. OTHER ISSUES:

Argument by petitioner

30. No anti-dumping duty is recommended in respect of certain grades/countries despite the existence of dumping margin. The Authority should impose anti-dumping duty wherever the dumping margin have been determined. For instance dumping Margin have been established for SBR 1700 series in case of imports from Taiwan and Turkey but no anti-dumping duty has been recommended. Similarly no anti-dumping duty has been recommended for imports from USA in respect of 1500 series. Anti-dumping duty be imposed wherever dumping margins have been determined but duty have not been recommended.

Examination by Authority

31. As per Anti-dumping rules, anti-dumping duties shall be levied not exceeding the margin of dumping and also that the duty shall be adequate to remove the injury to the domestic industry. Thus the quantum of anti-dumping duty is determined at the lower of dumping margin or the injury margin. The Authority had determined the dumping margin and injury margin in respect of exporters/countries and anti-dumping duties were recommended at the lower of dumping margin and injury margin.

The Authority had found, that in certain cases as cited by the petitioner above, the injury margin were negative implying that the landed value from such countries were non-injurious to the petitioner and therefore the Authority did not find justification to recommend the imposition of anti-dumping duty even though it was found that such countries/exporters are dumping.

Argument by petitioner

32. Quantum of anti-dumping duty is lower and is insufficient to remove the injury to the domestic industry. The base price adopted by Authority is below the cost of production as submitted by petitioner.

Examination by Authority

33. The argument of the petitioner is generic in nature and is not substantiated with facts. As per anti-dumping Rules, the Authority recommends the imposition of anti-dumping duty at the lower of dumping margin and injury margin and the Authority has adopted the same procedure in the instant case. The Authority has thus recommended the duties which are sufficient to remove the injury to the domestic industry. Regarding the argument that the base price adopted by Authority is below the cost of production submitted by the petitioner, the Authority had, while ascertaining the extent of anti-dumping duty necessary to remove the injury to domestic industry, relied-upon reasonable selling price of SBR in India, by considering the optimum cost of production at optimum level of capacity utilisation for the domestic industry on the basis of generally accepted accounting principles. The Authority has thus determined the reasonable selling price correctly.

Argument by petitioner

34. The quantum of duty lacks the co-relation with the import price of the product. The Anti-dumping duty has to be more in those cases where the import price is less so that the injury to domestic industry can be removed. However lower duty has been recommended where there is a lower price.

Examination by Authority

35. The extent of anti-dumping duty is determined at the lower of dumping margin and injury margin from a particular country/exporter. The quantum of duty thus can not have co-relation with the import price of the product where different countries/exporters are involved. Thus the argument of petitioner is not in accordance with anti-dumping Rules.

Argument by petitioner

36. The Authority should invoke the provision of retroactivity clause and impose anti-dumping duty from the date of initiation of the investigation, as there is a history of dumping in the instant case.

Examination by Authority

37. The Authority does not find it necessary to invoke the provision of retroactivity in the instant case.

Argument by petitioner

38. Anti-dumping duty be levied on SBR exports coming from various countries of EU as EU is a custom/trade union and there is no trade barrier among those nations. After adoption of single currency from this year, it is practically equivalent to single nation with free movement of goods and service.

Examination by Authority

39. The Authority observes that the petitioner had submitted the information on normal value, export price etc. from specified countries against which the Authority initiated investigation. The Authority does not consider it appropriate to extend the imposition of anti-dumping duty to various countries of EU at this stage as the other countries of EU were not provided an opportunity to defend the dumping allegation against them. The Authority notes that imposition of anti-duty on all EU countries at this stage would amount to extending the scope of investigation which is not in accordance with the Rules in the instant case.

Argument by petitioner

40. Cost of production of 1900 series is always more than the cost of 1500 series. In some cases the base price recommended for 1900 series is less than the base price recommended for 1500 series which needs to be re-calculated.

Examination by Authority

41. The Authority notes that the argument of the petitioner is not in accordance with the Anti-dumping rules. The amount recommended at Col. No. 5 of para 22 of preliminary findings have been determined keeping in view the export price from a country/exporter, dumping margin and injury margin etc. Therefore, the Authority observes that the amounts as referred by petitioner in their above argument has been correctly calculated and need not be re-calculated.

Argument by petitioner

42. Anti-dumping duty be imposed on export of product found dumped by an exporter or a manufacturer including exports by its joint ventures, subsidiaries or related exporters irrespective of the country from which the product is originating manufactured or exported.

Examination by Authority

43. The anti-dumping investigation are exporter/country specific and therefore the Authority observes that the argument is not in accordance with law .

Argument by Importer/Exporter

44. M/s Synthetics & Chemicals Ltd. (S&CL) have completely stopped producing SBR in view of severe financial constraints being faced by company. Thus by imposition of anti-dumping duty neither there will be a relief to S&CL nor to the importer resulting in unnecessary burden on economy. The Authority should therefore withdraw the anti-dumping duty.

Examination by Authority

45. The Authority has carried out the investigation in accordance with the Anti-dumping Rules in the instant case. Moreover, as per the practice, the Authority does not consider factors, which relate to beyond the period of investigation.

Argument by Importer/Exporter

46. The Authority has not recommended anti-dumping duty in respect of certain grade/countries despite the existence of dumping margin as the landed value of export from these countries/grades was equal to or more than the fair selling price determined for S& CL. Consequently no material injury could have been caused by the imports from these countries/grades. Thus no change is required in this regard.

Examination by Authority

47. The Authority agrees with the argument that wherever landed value are more that the reasonable selling price, no material injury could have been caused by such imports to petitioner.

Argument by Importer/Exporter

48. The exchange rate used for converting the foreign currency into Indian rupee should be the exchange rate notified by the Ministry of Finance for imported goods. Further the average exchange rate for the period of investigation should be the simple average of the exchange rates prevailing in the months in which the exporters had exported the product under consideration to India.

Examination by Authority

49. The Authority observes that petitioner has submitted the exchange rates prevailing during the investigation period as published in the Economic survey of India, which has been relied upon by the Authority. Regarding the argument that the average exchange rate for the period of investigation should be simple average of exchange rates prevailing in the months in which the exporters had exported the product, the Authority is not aware of when the goods were actually cleared by importer and therefore it may not be appropriate to apply the exchange rate as suggested.

Argument by importer/exporter

50. The weighted average custom duty for the period of investigation should be determined individually for each exporter with reference to the months in which the exports to India took place.

Examination by Authority

51. It has been the practice of Authority to adopt the weighted average custom duty for the period of investigation for the purpose of determination of landed value. Moreover, whereas the Authority is informed about the date/month of despatch of goods by the exporter, it is not known when the goods were actually cleared by importer. Thus calculation of weighted average custom duty with reference to the month in which the export to India took place may give misleading results and therefore it may not be appropriate to apply the weighted average Custom duty as suggested.

Argument by importer/exporter

52. There is denial of natural justice as these findings are based on material not made available to the interested parties so as to able to defend themselves as many information are treated as confidential.

Examination by Authority

53. In accordance with the Anti-dumping Rules, the Authority had maintained a public file which was kept open for inspection by any interested party throughout the period of investigation. The file contained information submitted by all interested parties on non-confidential basis. As per the Anti-Dumping Rules, the information submitted by any interested party on confidential basis and so considered as confidential by Authority can not be disclosed to other interested parties. Thus the argument is factually incorrect. The information treated as confidential by Authority are in accordance with anti-dumping rules.

Argument by Importer/Exporter

54. It is surprising and unfair that at the behest of a single monopoly supplier of SBR, the Directorate General of Anti-dumping and Allied duties has recommended to impose anti-dumping duty on SBR imports completely ignoring the genuine interest of hundreds of SBR consumers.

Examination by Authority

55. The argument is generic in nature. The Authority has carried out the investigation in accordance with the anti-dumping rules in the instant case.

Argument by Importer/Exporter

56. The petitioner is not in a position to meet the entire demand of industry in the country. Their request to the Govt. for anti-dumping duty is an attempt to increase their product price.

Examination by Authority

57. This is an admitted position that the petitioner is not in a position to meet the entire demand of industry in the country and this has been adequately dealt with in the preliminary findings. The argument that the request of petitioner to Govt for anti-dumping duty is an attempt to increase the product price is generic in nature. If the petitioner increases the price as alleged or feared by importers, any interested party can apply for review in accordance with anti-dumping rules so that the injury to the domestic industry if any can be re-assessed.

Argument by Importer/Exporter

58. The petition submitted by petitioner is either false or misleading or factually incorrect or material facts have been suppressed to the utter disregard of the interest of the consuming industry. Non-availability or availability of SBR at a high price will render workers unemployed. The claim of the petitioner that they are capable of producing total requirement of SBR in India is far from truth.

Examination by Authority

59. The argument is generic in nature and is not substantiated with facts. The Authority has carried out the investigation in accordance with the anti-dumping rules in the instant case.

Argument by Importer/Exporter

60. Anti-dumping duty should not exceed the dumping margin. However it is stated in the preliminary findings that in case the difference between landed value and reasonable selling price is higher than the dumping duty, the duty to be applied will be the difference figure, which is contrary to the Rules.

1657/31/99-3

Examination by Authority

61. The Authority considers that the duties have been recommended as per anti-dumping rules. The Authority has recommended the anti-dumping duties in similar ways in many other anti-dumping investigation, which has been accepted by the Govt. Thus the imposition of anti-dumping duties in the instant case is not contrary to the anti-dumping rules.

Argument by Importer/Exporter

62. Some of the exporters have stated that they have not exported SBR to India during the period of investigation and therefore they should be excluded from the preview of anti-dumping duty.

Examination by Authority

63. The Authority observes that such exporter may apply for a new shipper review as per anti-dumping rules.

Argument by Importer/Exporter

64. The Authority has not considered the interest of the end user industry. Any levy towards anti-dumping duty would not be in the interest of the consumer industry and would cause irreparable damage to the structure of the industry.

Examination by Authority

65. The argument is generic in nature. The Authority has carried out the investigation as per Anti-Dumping rules in the instant case.

Argument by Importer/Exporter

66. The preliminary findings are not clear and do not constitute a speaking order, as several issues raised have not been decided by Authority. These findings are beyond the jurisdiction of Authority under section 9 A (1) of the Custom Tariff Act 1975 as amended in 1995.

Examination by Authority

67. The Authority notes that speaking orders on the product under consideration, Like Article, Domestic Industry, Dumping & Dumping Margin, Injury, Causal Link etc. has been given. The Authority considers that it has taken into account all arguments and issues raised which can affect the determination of anti-dumping duties in accordance with anti-dumping duty rules. The Authority does not agree with the argument that the findings are beyond the jurisdiction of Authority under Section 9 A (1) of the Custom Tariff Act 1975 as amended in 1995.

Argument by Importer/Exporter

68. The landed value, which determines the reference prices, should be determined by adding only 1% of the CIF value towards landing charges. The present practice of charging 3% appear to be incorrect as all customs houses in India apply a uniform rate of 1% of the CIF value in order to arrive at the assessable value. The Authority had used only 1% in the EPDM case and therefore reference price should be revised.

Examination by Authority

69. None of the interested parties have submitted information on the actual landing and handling charges and therefore the Authority is following a consistent practice to add 1% towards landing charges and 2% handling charges while determining the landed value.

Argument by Importer/Exporter

70. The reference price in column 5 of para 22 of the preliminary findings includes either the dumping margin or the injury margin which ever is lower. Hence the indication of the lower of injury margin or the dumping margin in column 6 as the minimum anti-dumping duty amounts to a double levy of anti-dumping duty.

Examination by Authority

71. In preliminary findings notification, the Authority had stated that the anti-dumping duty shall be the amount mentioned in column 6, provided that the duty shall be difference between the amounts mentioned in column 5 and the landed value of imports per kg in case such difference is more than the amounts mentioned in column 6. The Authority does not consider that the fixation of duty in the preliminary findings amounts to double levy of anti-dumping duty. The argument appears to be factually and conceptually incorrect.

Argument by Importer/Exporter

72. The reference price should be at the CIF level only and should not take into account the prevailing level of custom duties.

Examination by Authority

73. In accordance with the Anti-dumping rules, the Authority is required to determine the amount which would be sufficient to remove the injury to the domestic industry. Such amount can be calculated only if the prevailing rates of custom duties are taken into consideration while arriving at the actual landed value during the period of investigation. Therefore, it is necessary that prevailing rate of custom duties are taken into account while determining the injury to the domestic industry as the injury to domestic industry is from the price at which the imported goods are available in the domestic market. Therefore the Authority does not consider it appropriate to determine the amount indicated in column 5 of the preliminary findings at CIF level.

Argument by importer/exporter

74. The Authority has not imposed anti-dumping duty on Germany and France. There are other exporters from France and Germany who had not co-operated and they should not be allowed to enjoy the benefit of non-cooperation as no anti-dumping duty is proposed on non co-operating exporters. The Authority should notify the reference price for non-cooperating exporter from Germany and France.

Examination by Authority

75 The Authority observes, that in the case of imports from Germany and France during the period of investigation, the landed value is significantly higher as compared to the reasonable selling price of domestic industry and thus such exports from Germany and France do not warrant imposition of anti-dumping duty. It is not demonstrated by any interested party that export price of any exporter from Germany and France is such which would cause injury to domestic industry and which warrant imposition of anti-dumping duty. The Authority in the circumstance does not find that the exports from Germany and France are causing injury to domestic industry.

Argument by importer/exporter

76. M/s JSR, an exporter from Japan has argued that they export SBR to India not directly but through various trading house viz. JTC and Mitsui. The Authority should indicate the reference price for the combination of JSR-Mitsui and JSR-JTC. The system of indicating combination rate for the producer-exporter is prevalent in USA.

Examination by Authority

77. It has been the consistent practice of the Authority to assess producers only and to recommend duty accordingly. So long as the importer is able to satisfy the custom Authority that the goods are produced a specific producer whose name is indicated while indicating the amount of duties in this notification, the Custom Authorities would impose anti-dumping duty accordingly. Also, it is not feasible to determine normal value of a trader, who can export goods of any producer. Therefore it is not feasible to levy and monitor anti-dumping duties on traders. The Authority therefore does not consider it appropriate to indicate reference price for the combination of the producer and trader.

Argument by exporter

78. The exporter from Korea has argued that their dumping margin and reference price should be determined in Korea currency.

Examination by Authority

79. It has been the consistent practice of the Authority to recommend anti-dumping duty in terms of Indian rupees and therefore the Authority does not consider it appropriate to recommend/impose duties in foreign currency.

I. FINAL FINDINGS

80. The Authority, after considering the foregoing, concludes that:

- (a) SBR has been exported from Japan, Korea RP, Turkey, Taiwan, USA, Germany and France has been exported to India below its normal value resulting in dumping of SBR;
- (b) the domestic industry has suffered material injury;
- (c) the causal link between dumping and injury is established.

81. The Authority confirms the preliminary findings with regard to imposition of Anti-dumping duty and recommends imposition of definitive anti-dumping duties on imports of SBR falling under custom sub-heading nos. 4002.19 of the Customs Tariff Act as specified under para relating to product under consideration originating in or exported from Japan, Korea RP, Turkey, Taiwan, USA. No anti-dumping duty has been recommended on exports from France and Germany or on 1500 series from USA, 1700 series from Taiwan and 1700 series from Turkey as such exports were not found to be causing injury to domestic industry. The anti-dumping duty shall be the amounts mentioned in column 6, provided that the duty shall be the

difference between the amounts mentioned in column 5 and the landed value of imports per Kg.
in case such difference is more than the amounts mentioned in column 6:-

Sl. No.	Country	Producer/Exporter	Grade	Amount (Rs. per Kg.)	Amount (Rs. per Kg.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	USA	All Exporters	1500 Series 1700 Series 1900 Series	--- 48.20 62.16	--- 3.48 6.77
2.	Taiwan	Taiwan Synthetic Rubber Corpn. Others	1500 Series 1700 Series 1900 Series 1500 Series 1700 Series 1900 Series	57.33 --- 57.90 58.33 --- 57.90	2.21 --- 3.20 3.20 --- 3.20
3.	Turkey	Petkim Petrokimya Others	1500 Series 1700 Series 1900 Series 1500 Series 1700 Series 1900 Series	57.50 --- 62.16 59.82 --- 62.16	8.26 --- 9.72 10.57 --- 9.72
4.	Korea	Korea Kumho Other Exporters	1500 Series 1700 Series 1900 Series 1500 Series 1700 Series 1900 Series	56.10 48.20 59.15 58.42 48.20 59.15	4.95 1.08 7.26 7.26 1.08 7.26
5.	Japan	JSR Corpn. Others	1500 Series 1700 Series 1900 Series 1500 Series 1700 Series 1900 Series	59.82 48.20 62.16 59.82 48.20 62.16	3.71 0.92 5.59 3.71 0.92 5.59

82. Landed value of imports for the purpose shall be the assessable value as determined by the customs under the Customs Act, 1962 and all duties of customs except duties levied under Section 3, 3A, 8B, 9 and 9A of the Customs Tariff Act, 1975.

83. Subject to above, the Authority confirms the preliminary findings dated 21.01.1999.

84. An appeal against this order shall lie to the Customs, Excise and Gold (Control) Appellate Tribunal in accordance with the Act Supra.

RATHI VINAY JHA, Designated Authority

